सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

07 मार्च, 2018

षोडश विधान सभा
नवम् सत्र

वृहस्पतिवार, तिथि 07 मार्च, 2018 ई0 / 16 फाल्गुन,1939(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य के मुख्य सचिव पर कोर्ट ने सम्मन किया है ।

अध्यक्ष : अभी तो प्रश्नकाल है । आप उठाइयेगा समय से ।
तारांकित प्रश्न संख्या-559, श्री राज कुमार राय ।

(व्यवधान)

डा0 रामानुज प्रसाद : राज्य के मुख्य सचिव को अभियुक्त बनाया गया है चारा घोटाला में ।

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण कुछ बोलते हुये वेल में चले आये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप जो भी कहना चाहते हैं उचित समय पर कहियेगा, अभी यह उचित समय है ? आप पुराने सदस्य हैं यह प्रश्न काल का समय उचित समय है ?

(व्यवधान)

प्रश्नकाल चलने दीजिये । आपलोगों का भी प्रश्न है, आप लोगों का भी प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय,माननीय सदस्यों का महत्वपूर्ण सवाल है, माननीय सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सभी माननीय मंत्री सरकार का उत्तर लेकर बैठे हैं, ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को नहीं पूछ कर के महोदय सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं और मैं जानना चाहता हूँ माननीय सदस्य से कि मुख्य सचिव जी का नाम किस मामले में आया है कम से कम स्थिति तो स्पष्ट करें । जो लोग पर सिर्फ नोटिश हुआ है तो इसके लिये इतना हंगामा कर रहे हैं और जो लोग जेल में बंद हैं महोदय, सजा काट रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है, यह भी तो बतलाना चाहिए माननीय सदस्य को ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग क्या चाहते हैं ? सदन नहीं चले, अगर यही चाहते हैं तो बतला दें। कोई समय पर बोलियेगा तब न ! प्रश्न काल में तो प्रश्न होता है । आप समय पर उठाइयेगा तो उस बात की नोटिश ली जायेगी, अभी आपकी कही हुई कोई बात प्रोसिडिंग्स में नहीं जायेगी न, क्योंकि अभी प्रश्नकाल है । अभी प्रश्न काल है और अगर आप चाहते हैं कि माननीय सदस्यों के प्रश्न नहीं लिये जायं तो यह आपका फैसला है । आप.....

(व्यवधान)

टर्न-2/ज्योति/07-03-2018

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग अपनी अपनी जगह पर जाईये ।

(व्यवधान)

विजय प्रकाश जी, प्रश्नकाल में वक्तव्य होता है क्या ? आप जाईये न अपनी जगह पर, अपनी जगह पर जाकर बोलिये ।

(व्यवधान)

अपनी जगह पर जाईये , समय पर उठाईयेगा, नोटिस ली जायेगी ।

(व्यवधान)

अपनी जगह पर जाईये, आपकी बात हम सुनेंगे लेकिन सुनने दें तब तो ?

(व्यवधान)

अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं ? अपनी जगह पर जाकर कुछ बोलिये तो हमलोग भी सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी जगह पर जाकर कुछ बात कहें तो सरकार सुनेगी और माननीय सदस्य अगर वेल में आकर कुछ बात कह रहे हैं तो न आसन को सुनायी पड़ रहा है और न सरकार को कुछ सुनायी पड़ रहा है और इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा नहीं होने देते हैं और आरोप हमेशा लगाते हैं कि सरकार समस्या का हल नहीं करना चाहती है तो सरकार तो समस्या के हल के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब लेकर बैठी है और सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं और कोई भी बात अगर उठानी है तो अपनी जगह पर से उठायेंगे तो जवाब भी दिया जायेगा लेकिन वेल में आकर हंगामा करने से समस्या का हल नहीं हो सकता है इसलिए माननीय सदस्य हम भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अपनी जगह पर जा करके बात को रखें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब अगर आप नहीं चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले तो सभा की कार्यवाही ....

(व्यवधान)

सुनिये न कबतक स्थगित करें ? वह तो सुनियेगा न ? आप अपनी जगह पर जाईये ।

(व्यवधान)

सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-3/07.3.2018/बिपिन

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, आज कृषि विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	-	59 मिनट
जनता दल(युनाइटेड)	-	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	20 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	-	02 मिनट
निर्दलीय	-	03 मिनट

जैसा कि मैं बराबर कहता हूं क्योंकि मैं देखता हूं कभी-कभी बोलने के क्रम में माननीय सदस्य जो हमें बोलते हैं, कहते हैं कि हमारा इतना समय है लेकिन इसी समय में से काट कर सरकार को भी उत्तर के लिए समय दिया जाता है । इसलिए सरकार के उत्तर में जो समय जाता है वो अनुपातिक ढंग से, क्योंकि सरकार का उत्तर तो सभी दल के माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर होता है, इसलिए अनुपातिक ढंग से जो विभिन्न दलों को समय आवंटित होते हैं, उसी में सामंजित किया जाता है ।

माननीय मंत्री, कृषि विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''कृषि विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 27,49,77,93,000/- (सत्ताइस अरब उनचास करोड़ सतहत्तर लाख तिरानवे हजार) रूपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: इस मांग पर श्री भोला यादव, श्री रामदेव राय, श्री मो0 नेमतुल्लाह, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री महबूब आलम एवं श्री ललित कुमार यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं एवं जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री भोला यादव का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री भोला यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री भोला यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाए ।''

महोदय, माननीय मंत्री जी जो पेश किए हैं आय-व्यय का ब्यौरा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष से इस वित्तीय वर्ष में सौ करोड़ रूपये से अधिक की कटौती कर दी गई है । लगता है माननीय मंत्री जी का प्रभाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नजर में कम पड़ गया है । उनके हिस्से में भारी कटौती हो गई है । महागठबंधन की जब सरकार थी, इसका बजट ज्यादा था। माननीय प्रेम कुमार जी जब मंत्री बने तो इनके विभाग में कटौती हो गया है सौ करोड़ का । यह दु:खद है । जब सौ करोड़ का कटौती हो रहा है तब इसकी मांग क्यों नहीं घटाई जाए ? इसकी मांगी इसीलिए घटाई जाए कि सरकार को पैसे की जरूरत उतना नहीं है जितना इन्होंने दिया है ।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, यह विभाग लंबे अनुदान की श्रृंखला की कड़ी में चल रहा है और इस अनुदान की श्रृंखला में मालोमाल हो रहे हैं बड़े-बड़े उद्योगपति । एक छोटा मिसाल हम देना चाहते हैं । एक कुदाल की कीमत बाजार में 120/-रूपए से 125/-रूपए है और इनका विभाग उस कुदाल को खरीदता है ढ़ाई सौ रूपया में और फिफ्टी परसेंट अनुदान देकर किसान को मुहैया कराता है 125 रूपया में, तो आखिर यह 125/-रूपया में जो बाजार में 120 से 125 रूपया में उपलब्ध है, वह सामान ढ़ाई सौ रूपया में खरीदते और किसी-न-किसी व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए ये करते हैं । तो इससे कहीं-न-कहीं हमारे ऊपर में, हमारे सरकार के ऊपर में, हमारी जनता के उपर में बोझ आ रहा है । ऐसे ही हमलोग कर्ज से डूबे हुए हैं महोदय । 2016-17 का जो डाटा है, 2016-17 के डाटा में जो ऋण की स्थिति है, 19.64 परसेंट था और अभी 2017-18 में जब महागठबंधन की सरकार गई, एन.डी.ए. की सरकार आई, एकाएक ऋण बढ़ा लिए ये लोग । ऋण ज्यादा कर दिए । वह ऋण हो गया 26.25 परसेंट और इनका जो टारगेट है, 2020-21 में जाकर 27.50 हो जाएगा । कहीं-न-कहीं ये कर्ज को बढ़ा रहे हैं । मतलब कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। तो इस चीज को रोकना है । एक छोटा-सा और हम उदाहरण देना चाहते हैं । किसानों की क्या दुर्गति है, इससे सभी लोग वाकिफ हैं क्योंकि जितने मेंबर हैं, प्राय: किसान परिवार से यहां आए हैं, शहरी वाले को छोड़कर । तो किसान परिवार से जो लोग आए हैं, किसान की क्या दुर्गति है, उत्तर बिहार बाढ़ को झेल रहा है, दक्षिण बिहार सुखाड़ झेल रहा है। तो किसानों के उपर जो बीत रहा है उसका कोई सुधि लेने वाला नहीं है । हमलोगों के क्षेत्र में इतना भारी बाढ़ आया, एक रूपया कृषि फसल का जो मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाया और कुल मिलाकर देखिए तो किसानों की स्थिति दिन-पर-दिन बदतर होते जा रहा है । एक उदाहरण हम देना चाहते हैं महोदय । किसानों का एक बड़ा आय का साधन था महुआ । महुआ का पेड़ हरेक किसान के पास, हमलोगों के इलाके से लेकर जमुई इलाके तक सौ-पचास पेड़ हरेक के पास था और महुआ का जो फूल चूता था, उसको लोग सूखा कर बाजार में बेचते थे । उससे अच्छी आमदनी लोगों को आती थी । जब से दारू की नीति आई

है, तब से किसान महुआ चुनना बंद कर दिए हैं । राज्य का बहुत बड़ा राजस्व का क्षति हो रहा है महोदय । मैं माननीय मंत्रीजी से मांग करूंगा आपके माध्यम से, महुआ क्रय केंद्र खोला जाए सरकारी स्तर पर ताकि किसानों को उचित लाभ मिल सके । महुआ का जो फसल बर्बाद हो रहा है, उससे लाभ मिल सके । कुल मिलाकर इनका बजट कहीं-न-कहीं कटौती के लायक है । कटौती होते जा रहा है । मैं इस कटौती के समर्थन में हूं और कटौती होना चहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : डॉ0 रामानुज प्रसाद ।

श्री भोला यादवजी ने भी लगभग 10 मिनट ले लिया जो आपकी पार्टी ने आवंटित समय दिया है । इसलिए आपको 11 मिनट में ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कृषि, किसानी एक ऐसा महकमा है, ऐसा है कृषि का क्षेत्र जिससे न सिर्फ अपना बिहार, अपना देश, बल्कि कोई भी दुनिया का देश कृषि को इंकार करके नहीं चल सकता है । कृषि का उपज ही है कि सभी मानव जो है वह खाकर जीते हैं बल्कि ये अन्न के बगैर, दुनिया में जितना भी नोट उपजा ले कोई लेकिन अगर अन्न नहीं उपजाता है तो मैं समझता हूं और यह मान्यता है कि अन्न के बगैर कोई मानव जिंदा नहीं रह सकता ... क्रमश:

टर्न: 04/कृष्ण/07.03.2018

डा0 रामानुज प्रसाद : (क्रमश:) यह कृषि सम्पूर्ण जगत का प्रत्यक्ष तथा प्रथम जीवनाधार है । कृषि को कोई भी देश इंकार नहीं करता । धरती पर सारी लड़ाई दो जून की रोटी के लिये है । सारी लड़ाई, जद्दोजहद दो जून की रोटी के लिये ही हो रही है और होता रहा है । कोई भी जीवन कृषि उत्पाद से अलग नहीं है । अत: हम यह कह सकते हैं कि पारंपरिक तौर पर कृषि न सिर्फ आजीविका का हमारा प्रमुख स्रोत रहा है बल्कि मनुष्य जब बजूद में आया, जब उसका सांस्कृतिक विकास होने लगा, जब वह व्यक्ति से समाज की ओर बढ़ने लगा तब कृषि कार्य को लोग करने लगे और कृषि ही जीवनधारा बनी, कृषि ही रोजगार का मुख्य जरिया बना । अत: बिहार में भी ग्रामीण आबादी को कृषि से रोजगार प्राप्त होता रहा है । अध्यक्ष महोदय, आज सदन में हम बिहार की कृषि पर चर्चा कर रहे हैं । मैं बार-बार यह कहता हूं कि बिहार की सरकार और बिहार के सरकार की मुखिया इवेंट मैनेजर अच्छे हैं, जिन्होंने कृषि रोड मैप बनवाया, दो-दो महामहिम राष्ट्रपति को बुला करके जश्न मनाया, कलाम साहब को मोडल बनाया गया, अभी महामहिम कोविंदजी को बुलाया गया । इसके बीच में भी लोग आये । लेकिन हश्र क्या हुआ ? इस बार का जो एलॉकेशन है, माननीय सदस्य भोला जी कह रहे थे कृषि पर जो हमारा एलॉकेशन है, जो अन्य राज्य हैं, उन सभी राज्यों से कृषि पर कम एलॉकेट किया है । हमारी सरकार ने जो बजट लायी है, वह देश के 18 राज्यों से 6.4 प्रतिशत कृषि पर हमारा एलॉकेशन कम है । हम कैसा बिहार बनाना चाहते हैं ? कौन-सा रोजगार का साधन हम बिहार के लोगों को देना चाहते हैं ? कौन-सा रोजगार हमने खड़ा कर लिया ? कौन-से कल-कारखाने हमने लगा लिये कि हमने कृषि को प्राथमिकता से हटा दिया । अध्यक्ष महोदय,

यह विदित सत्य है, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं । हमलोगों की भी समझ थी कि मुख्यमंत्री जी आए हैं तो अपने विजन को मिशन बनायेंगे । भारत सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं । महोदय, मैं एक वाक्या सुनाना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, हमलोग बहुत शुरूआती दौर से राजनीति में जद्दोजेहद कर रहे थे । उन दिनों डा0 कुमार विमल वी0सी0 हुआ करते थे, हम उनके यहां एक पैरवी में गये थे । हम चाय पी रहे थे उनके साथ । कुछ उनसे बातें हुई । बात सुनकर उन्होंने कहा कि आपलोग भी राजनीति में बिगनर्स हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। नीतीश जी के जो कार्य-कलाप हैं, जो एक्टीविटीज है, आपलोगों को भी सीखना चाहिए। उन्होंने एक घटना बताई कि नीतीश जी जब भारत सरकार में कृषि मंत्री बने थे और उनका स्पीच हो रहा था, हम भी उस समय पार्लियामेंट सुन रहे थे तो लगा कि नीतीश जी का जो विजन है, निश्चित तौर पर जो बातें करते हैं, शब्दों का जो चुनाव वे करते हैं, उनका शब्दों का जो प्लेसमेंट है, इनमें एक बड़ा नेता होने का गुण झलकता है, परिलक्षित होता है । सबलोगों को लगा । वे मुख्यमंत्री हो भी गये । लेकिन मुख्यमंत्री तो हो गये । तो मुझको लगता है कि विजन चाहे जो भी हो, लेकिन मिशन चेंजर हैं ।

(इस अवसर पर सभापति श्री हरिनारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया।)

सभापति महोदय, मिशन इनका बदलता रहता है और मिशन बदलता है तो इसका खामियाजा राज्य भुगत रहा है और आगे भी भुगतेगा । अभी जिस चीज का ढिंढोरा पीट रहे हैं, सात निश्चय, सात निश्चय । सात निश्चय में कृषि को और कृषि रोड मैप को कहीं स्थान ही नहीं मिला । कभी इसका भी ढिंढोरा इन्होंने पीटा था कि देश के तमाम जनता की थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, यह हमारा सपना है । अब यह बोलते ही नहीं, बल्कि एलॉकेशन कम कर दिया इन्होंने । सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार अगर सच्चे मायने में चाहती है कि यह राज्य तरक्की करे तो कृषि को उन्नत करने की जरूरत है । हमारे जो सभी राज्यवासी हैं, उन तक सुलभ करने की जरूरत है और इसको ऐसा आकर्षक बनाने की जरूरत है कि जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, वह रोजगार कृषि के क्षेत्र में तलाशें । महोदय, आज कृषि का यह हालत है कि आम पढ़े-लिखे लोग तो किसानी नहीं करना चाहते, नहीं करते बल्कि किसान का बेटा भी किसान नहीं बनना चाहता है । कैसे होगा कृषि ? कैसे मोडल बनेगा ? कोई किसान का बेटा अगर पढ़-लिख लिया और उसको कहा जाय कि खेती का काम करो, किसानी में काम करो, कृषि कार्य में लगो तो वह तैयार नहीं होता है । यह हालत है अपने बिहार में कृषि का । इसी देश में दो-दो मुख्यमंत्री हो चुके हैं जो अपने-अपने प्रांत में कृषि के मामले में न सिर्फ उन्नत किया, मजबूत किया, बल्कि देश को भी अन्न के मामले में आत्मनिर्भर किया- प्रताप सिंह कैरो, मोहन लाल सुखाड़िया। लेकिन वे गेम चेंजर, नेम चेंजर, इशु चेंजर नहीं थे, कंसेन्ट्रेट करते थे अपने इशु पर और आज देख रहे हैं उस समय का पंजाब पूरे देश को अन्न खिलाता है, अगर अन्न भारत से कहीं निर्यात होता है तो पंजाब, हरियाणा से होता है । बालू का प्रदेश, डेजर्ट स्टेट राजस्थान में गुलाबी शहर बसाने का काम किया था मोहन लाल सुखाड़िया ने और हमारे यहां ? हमारी एक विडम्बना है कि आधा हमारा बिहार बाढ़ से बह जाता है और आधा हमारा बिहार सूखता

है । कैसे होगा ? अगर हम चाहते हैं कि सही माने में किसान तरक्की करे तो हमको सिस्टम सुधारना होगा और हमको यह करना चाहिए कि किसान के लिये जो सबसे आवश्यक है कि पहले उसको अच्छा बीज मिले, अच्छी पैदावार हो, जब पैदावार हो तो उसको बाजार मिले, उसको अच्छी कीमत मिले, उसकी गारंटी हो और उससे ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था हो, फसल की बचाव की व्यवस्था हो । इस पर सरकार का कहीं कुछ नजरिया नहीं है । राष्ट्रपति को बुला करके, सुन्दर किताब छपवा करके, किताब तो बहुत आकर्षक लगता है, कृषि रोडमैप का फोटो बहुत अच्छा लगता है जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी रोज-रोज बंडी बदल रहे हैं, वे कृषि मंत्री वाला भी बंडी अब पहन लिये, रोज-रोज बंडी बदलने वाले के साथ मन बदल गया या डरकर बंडी बदल रहे हैं । लेकिन कृषि का जो मामला है, उसमें सुधार होता नहीं दिखता है । सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात की गारंटी करे कि जो भी योजनायें चल रही है कृषि के मामले में, वे योजनायें सही ढंग से सरजमीं पर उतरे, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो । इम्प्लीमेंटेशन के ग्राउंड पर सरकार की जो स्थिति है, मैं बताना चाहता हूं । सभापति महोदय, योजनायें तो हैं, योजनायें बनी भी हैं, बनती रहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि क्रियान्वयन के ग्राउंड पर माननीय मंत्री जी, जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, आप योजना बना रहें हैं मिट्टी जांच हेतु लेकिन मिट्टी जांच हेतु मोबाईल लेबोरेट्री कहां चल रहा है ? यहां आने के पहले हमने इसकी इन्क्वायरी की । आप योजना बना रहें है कि रब्बी और खरीफ मौसम में सूची तैयार करना, कौन आपका कर्मचारी सूची तैयार करता है । दिनभर वे या तो कैसे बेचें, आप अनुदान देते है, उसमें कैसे लूट मचावें, इसमें लगे रहते हैं ।

क्रमशः

टर्न-5/सत्येन्द्र/7-3-18

डॉ0 रामानुज प्रसाद(क्रमशः) अभी अभी समाचार में चल रहा है, अगर हमारा सिस्टम काम कर रहा होता तो जो मक्का का बीज हमने किसानों को दिया, मक्का का बीज जो आपने दिया, आज उसे लेकर पूरे बिहार के किसान त्राहिमाम में है, उनके फसल में एक में भी मक्का का बाल नहीं आया, किसी में बाल आया तो दाना नहीं आया और आप कह रहे हैं कि जांच कमिटी बना दी गयी है । ये जांच कमिटी बनाने से अगर किसानों को मिल जायेगा तो आप इसकी घोषणा करिये कि हम उसका मुआवजा देंगे और दोषियों को सजा देंगे और यह आगे से रूके भी, फसलों के कटनी हेतु यंत्र, लघु सिंचाई की व्यवस्था करना, कृषकों के बीच प्रचार प्रसार करना, यह सब कहां होता है । कृषि यंत्रों का प्रचार-प्रसार कहां होता है अगर लगते भी हैं एक्जीविशन तो राज्य में आप यहां लगा देते हैं भेटनरी कॉलेज के मैदान में । जिलों में आपके जो मूल किसान हैं उनके बीच जबतक आप नहीं जायेंगे, हमारे जो कम पढ़े लिखे किसान हैं, अनपढ़ किसान हैं उनके बीच जो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलोजी है, जो हमारा रिसर्च है या दुनिया का रिसर्च है उसको हम नहीं ले जायेंगे तो किसान को क्या फायदा होगा। आपका परिणाम वाला तो कोई कार्यक्रम नहीं है। केवल कागज पर बनाये और परिणाम आपने नहीं खोजा तो मैं समझता हूं सभापति महोदय कि फलाफल बेहतर नहीं आ सकता है । ये जितनी योजनाएं इनकी चल रही है सबकी सूची है लेकिन हमलोग जितने भी यहां एम0एल0ए0 बैठे हैं,

हमलोग अपने अपने क्षेत्र से आते हैं, कहीं सरजमीन पर यह योजना चलता हुआ दिखलाई दे तब उसके परिणाम की बात होगी ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें, आपका समय खत्म हो गया ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: थोड़ा समय सभापति महोदय और दिया जाय । बोलना तो और था लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, आज और दो विभाग भी है, एक तो महत्वपूर्ण विभाग छूट रहा है उसके मंत्री जी बहुत कह रहे थे तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये मद्य निषेध, निबंधन के मंत्री जी आज पूरा देश यह देख रहा है कि साहब मन की बात करने वाले मन की बात कैसे करते हैं और उद्देश्य में मन की बात करने वाले हैं और अपने राज्य में मन की बात थोपने वाले हैं । हमारे जो राज्य के मुखिया हैं, इनके मन में जो बातें आ जाती हैं थोंप देते हैं लोगों पर । कभी ये गांव गांव शराब पहुंचा देते हैं और कभी कहते हैं शराबबंदी होगा । शराबबंदी का हाल यह है कि ये कहते रहते हैं सरकार के मुखिया, सरकार के लोग कि न हम बचाते हैं, न फंसाते हैं लेकिन हमलोगों को जो अनुभव हो रहा है कि ये बचाते भी हैं और दूसरे को फंसाते भी है । इसका तो उदाहरण है, अभी दो दिनों से चल रहा है, तीन दिनों से चल रहा है कि साहब एक मंत्री जी के सामने यह परोसा हुआ है, मंत्री जी भी उस दिन से दिखलाई नहीं दे रहे हैं लेकिन कहां गये, अभी तक एक बयान नहीं आया माननीय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान तक नहीं आया । अभी एक एम0एल0ए0 को टी0भी0 में दिखलाया गया कि रामगढ़ के एम0एल0ए0 मंच पर शराब पीकर नाचने वालों के साथ हैं । यह क्या हो रहा है इसलिए हम कहना चाहते हैं..

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): अब समाप्त करें । श्री उमेश सिंह कुशवाहा।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा: महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा जो सदन में मांग प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ । महोदय, बिहार की आबादी का 90 प्रतिशत लोग गांव में बास करते हैं और बिहार प्रदेश का आत्मा गांव में बास करती है और 79 प्रतिशत लोगों का जीवन यापन उनकी जीविका कृषि तथा कृषि पर आधारित है । आज धरती के भगवान कहे जाने वाले किसानों के हाल एवं हालात को सुधारने के लिए एवं उनको आर्थिक प्रगति पर लाने के लिए हमारी सरकार अग्रसर है । महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बतलाना चाहता हूँ कि पहले के किसान मेहनत तो करते थे लेकिन मेहनत के हिसाब से उनको फसल का उत्पादन नहीं हो पाता था और इसका मुख्य कारण था प्रमाणित बीज नहीं उपलब्ध रहना । महोदय,आज मुझे याद है करीब 10-12 वर्ष पहले बिहार में गेहूं का बीज अन्य प्रदेशों से लाकर जैसे तैसे मार्केट में बेचा जाता था और किसान भी बीज की गुणवत्ता पहचाने के मामले में जानकार नहीं थे और उस समय विभाग में भी शिथिलता थी, उस समय के किसान का हाल था कुर्त्ता फटाफटा, धरती के भगवान को आधा भोजन मिलते सुबह शाम, यही हालत था उस समय के भारतीय किसान का लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने पहला कृषि रोड मैप 2008 में बनाकर कृषि प्रक्षेत्रों के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का काम किया, शुरूआत किया और बिहार के किसानों को खुशहाल करने का पहल किया । आज खुशी हमें इस बात का है कि आज बिहार में सभी जगहों पर प्रमाणित बीज उपलब्ध है । चाहे राज्य बीज निगम हो या अन्य जगह, सभी जगहों पर

गुणवत्ता वाली बीज आज उपलब्ध है । महोदय, गुणवत्ता गेहूं का बीज के कारण आज गेहूं के फसल में आपार वृद्धि हुई और अनुमान भी है कि जो फसल अभी लगी हुई जिसका अनुमान किया जा रहा है कि अच्छा फसल होगा । महोदय, माननीय सदस्य मकई का चर्चा कर रहे थे । महोदय, वह जो कम्पनी थी वह हमारे सरकार के लिस्ट में नहीं था, बाहरी कम्पनी आकर मकई का बीज यहां बेच डाला । महोदय, हमारी सरकार द्वारा जो कम्पनी को लिस्टेड किया गया है उसका बीज जो प्रमाणित बीज है, वह बीज से निश्चित रूप से बिहार में फसल उत्पादन बढ़ा है । महोदय, धान के खेती में भी काफी वृद्धि हुई है । आज यहां बड़े बड़े ब्यालर राईस मिल की स्थापना हुई है, बड़ी तेजी से और स्थापना हो रही है महोदय, कृषि के क्षेत्र में जो पॉल्ट्री व्यवसाय है यह काफी बिहार में बढ़ा है, गुणवत्ता उसमें भी आयी है, काफी वृद्धि हुई है। महोदय, कम लागत से किसान कम समय में पॉल्ट्री व्यवसाय कर अच्छी आमदनी कर लेते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य से प्रभावित होकर बाहर की कई बड़ी कम्पनी यहां आकर के जो छोटे छोटे हमारे किसान हैं उसको लाभान्वित करा रहे हैं। महोदय, आज जो बिहार कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, आत्मनिर्भरता ही हमारी सबसे बड़ी सफलता है इसका श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है जिन्होंने प्रथम कृषि रोड मैप 2008 में, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 में और अभी हाल के दिन 9 नवम्बर, 2017 को तीसरा कृषि रोड मैप का महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा उसका शुभारम्भ करवाया गया । महोदय, जो अभी वर्ष 2017 और 2022 के तीसरे कृषि रोड मैप की शुरूआत हुई है, महोदय, उसका खासियत मैं बतला रहा हूँ जो तीसरा कृषि रोड मैप है, इसमें किसानों की जो सारी समस्याएं है वह सब समस्या का निजात कराया गया हैं, उसमें अनुदान का और सभी फसल बीमा बगैरह और अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मांस मछली सभी में गुणात्मक सुधार का लक्ष्य रखा गया है ।(क्रमशः)

टर्न-6/मधुप/07.03.2018

... क्रमशः ...

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, कृषि के क्षेत्र में भी अभी कृषि फीडर बिजली आपूर्त्ति के लिए, उसको कार्य रूप दिया जा रहा है । यह सारी महत्वाकांक्षी योजना जो है, सरकार के द्वारा जो चलाये जा रहे हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने इन सारे कार्यक्रम को लागू किया । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि भारतवासी के हर थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, वह सपना साकार होते हुए दिखाई दे रहा है ।

महोदय, मैं मंत्री जी से विनम्र निवेदन के साथ कुछ सुझाव देना चाहता हूँ ताकि हमारे बिहार का किसान और खुशहाल हो सके । महोदय, बाजार समिति में मल्टी कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होनी चाहिये ताकि हमारा जो कच्चा माल है, उसका जो भाव है, न मिलने पर भंडारण किया जा सके । महोदय, बाजार समिति में किसानों के लिये हेल्पलाईन की व्यवस्था हो जिससे किसान का उत्पादन का अन्य बाजार में जो मूल्य है, उसकी जानकारी समय-समय पर उसको मिल सके । महोदय, पॉल्ट्री में ब्यॉलर फार्मिंग के लिये, 2 हजार

क्षमता का मुर्गा फार्म बनाने पर अनुदान हो या मनरेगा से उस फार्म को बनाया जाय ताकि हमारे किसान भाई को रोगजार का अवसर प्राप्त हो सके ।

बिहार में उत्पादित जो बीज है, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ वैशाली जिला में कोबी का बीज, सबसे पहले बीज होता है, हमारे यहाँ जो बीज है, जैसे फूलकोबी, लाल साग, नेनुआ, लौकी, मटर, अन्य प्रदेश में इसके बीज का काफी डिमांड है । इसके लिये मैं आग्रह करूंगा कि इसके लिये वैज्ञानिक लोग से बीज विकसित करने के लिये जानकारी एवं प्रशिक्षण दिलवाने की कृपा की जाय । हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो कोबी का बीज अगात होता है, पूरे वर्ल्ड लेवेल पर हमारे यहाँ के बीज का काफी डिमांड है । हमारे यहाँ का बीज ही बहुराष्ट्रीय कम्पनी, अलग-अलग देश का कम्पनी लेकर इसको नई तकनीकी देकर उसको बीस गुणा ज्यादा रेट पर बेचता है । इसलिये महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि उसको विकसित करने के लिये किसानों को इसका प्रशिक्षण दिलवाया जाय । हमारे यहाँ जो शीतगृह है, कोल्ड स्टोरेज, उसमें जो बिजली खर्च होता है, इसके लिये मैं चाहूँगा कि यह कृषि से जुड़ा हुआ है, इसका कृषि टैरिफ में बिजली का रेट रखा जाय ।

मैं पुनः माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी को जिन्होंने सदन में माँग प्रस्ताव रखा है, इस माँग का मैं समर्थन करता हूँ, पुरजोर समर्थन करता हूँ । हमारे क्षेत्र में महोदय, एक फर्म है वहाँ काफी जगह है, लगभग 20 एकड़ का एक जमीन है जो बिहार सरकार का जमीन है, हम चाहेंगे कि वहाँ कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हो वैशाली जिला में, जमीन वहाँ उपलब्ध है । इसके लिये मैं मंत्री महोदय से माँग करता हूँ । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

श्री मनोज कुमार : सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए माननीय मंत्री, कृषि, बिहार सरकार, आदरणीय प्रेम कुमार जी के द्वारा जो बजट की माँग को रखा गया है 2749 करोड़ रूपये का, उसके समर्थन में और विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं बोलने के लिये आज खड़ा हूँ।

महोदय, मैं तीन मुख्य बिन्दुओं पर अपनी बातों को कहना चाहूँगा । पहला, केन्द्र की एन0डी0ए0 सरकार के द्वारा जो बजट इस बार 2018-19 में लाया गया है, जो शायद किसानों के लिये उपहार स्वरूप साबित होने जा रहा है । लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 54 हजार करोड़ रूपये का बजट माननीय राधामोहन जी ने सदन के सामने वित्त मंत्री के माध्यम से रखा । साथ-साथ मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूँगा कि केन्द्र की सरकार ने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले पाँच सालों में 2014 से 2019 के बीच का जो बजट का ले-आउट संसद में रखने का कार्य किया है, मैं केवल यह मंशा बतलाना चाहता हूँ कि हमारी मंशा किसानों के प्रति क्या है, खेती के प्रति क्या है और उसका तुलनात्मक अध्ययन मैं करवाना चाहता हूँ आपके माध्यम से सदन को कि यू0पी0ए0 सरकार ने 2009 से 2014 के बीच में कृषि बजट में जो प्रावधान किये थे, अगर आप देखेंगे तो पूरे सदन को इस बात के लिये धन्यवाद देना पड़ेगा वर्त्तमान नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को, राधामोहन जी को कि पिछले पाँच सालों में 2009-14 के बीच में जहाँ यू0पी0ए0 सरकार ने कृषि बजट के

लिये 1 लाख 21 हजार करोड़ रू0 का प्रावधान किया था तो आज की वर्त्तमान ए0डी0ए0 सरकार ने इन पॉच सालों में 74 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये लगभग 2 लाख 10 हजार करोड़ रू0 का प्रावधान किसानों के लिये कृषि के क्षेत्र में किया है । अब इसके आंकड़े अगर विभागवार आप लेंगे तो मैं उसको भी सदन के सामने रखना चाहूँगा कि क्रॉप इंश्योरेंस में 2009 और 2014 के बीच पॉच सालों में जहॉ 6182 करोड़ रू0 की व्यवस्था की गई थी तो इस एन0डी0ए0 सरकार ने अभी पॉच सालों में लगभग 436 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 33162 करोड़ रू0 का प्रावधान किया है । इसी तरह माइक्रो एग्रीकल्चर में आयेंगे तो 298 प्रतिशत की वृद्धि है, सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट में आयेंगे तो 871 प्रतिशत की वृद्धि है, एग्रीकल्चर मैकेनिज्म में आयेंगे तो लगभग 846 प्रतिशत की वृद्धि है । अगर सबमीशन पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आयेंगे तो लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में 131 प्रतिशत की वृद्धि है और रेन-फेड डेवलपमेंट एरिया में लगभग 700 प्रतिशत की वृद्धि है। ऐसे कई आंकड़े हैं, इसको मैं रख देना चाहूँगा, मैं सदन का समय इस विषय पर अधिक नहीं लेना चाहूँगा । साथ-साथ, इस बार केन्द्र की सरकार ने जो बजट पेश करने का कार्य किया है, उसकी जो विशेषता है, उसके बारे में बताऊं कि कई ऐसे फंड इस बजट के 54 हजार करोड़ के ले-आउट के अलावा जो प्रावधान किये गये हैं, उसका जो फायदा हमारे बिहार की सरकार को मिलने वाला है, हमारे बिहार के किसानों को मिलने वाला है, इसके लिये माइक्रो इरीगेशन फंड में भी लगभग 5 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान है । यह सोचने की बात है कि हम कितने नीचे तक जाकर किसानों के हित के बारे में सोचते हैं । सबसे बड़ी बात DIDF (Dairy Infrastructure Development Fund)में हमलोगों ने 10881 करोड़ रूपये, जिसका सर्वाधिक भाग लाभ बिहार के किसानों को मिलने वाला है क्योंकि बिहार में पशुपालकों की संख्या मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश से किसी मामले में या अन्य राज्यों से कम नहीं है । इसलिये आपको धन्यवाद देना होगा इस सोच के बारे में । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे साथी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे, बाजार समिति के बारे में बात कर रहे थे और ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे हम विपणन की, मार्केटिंग की कैसे व्यवस्था कर सकें, उसके लिये भी लगभग शुरूआती कदम के तौर पर 2 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है । फिशरी के क्षेत्र में, छोटे-छोटे मुर्गी पालन के क्षेत्र में, इसके लिये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का निर्माण कराया गया है, उसके लिये भी 10 हजार करोड़ रू0 की व्यवस्था की गई है । यह केन्द्र की जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं जिसका सीधा-सीधा लाभ बिहार सरकार को मिलने वाला है क्योंकि आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रेम कुमार जी हमारे कृषि मंत्री है, माननीय राधामोहन जी वहॉ केन्द्र में कृषि मंत्री हैं । इसका सर्वाधिक लाभ, पूरी उम्मीद के साथ, पूरे दावे के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस बजट का सर्वाधिक लाभ जो मिलना है, वह बिहार की सरकार को मिलना है । इसके साथ-साथ मैं एम0एस0पी0 के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इस बार बजट में इस बारे में काफी गम्भीरता से मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिये सोचा गया है, किसानों की आमदनी को दोगुणा करने का लक्ष्य नरेन्द्र मोदी जी ने यह संकल्प के साथ जो ऐलान किया है, तो हम भी उस संकल्प को सिद्धी में बदलने के लिये हमारा पूरा

तंत्र, हमारी पूरी व्यवस्था लगी हुई है । इसके लिये भी नीति आयोग को राज्य की सरकारों के साथ में किसानों का लागत क्या है और कम से कम उससे डेढ़-गुणा उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके । इसकी दिशा में काम किये जा रहे हैं जिसका परिणाम अभी आना है ।

सभापति महोदय, मैं अपने साथियों को यह बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कई ऐसे कोऑर्डिनेशन जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से नीति आयोग जो कर रही है जिसका सीधा का सीधा लाभ किसानों को मिलने वाला है, वह दिन अब दूर नहीं है जब हम 2022 के लिये किसानों की आमदनी दोगुणा बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है, उसे हम पाने की ओर रास्ते में निकल पड़े हैं । मैं आपको बताना चाहूँगा इस बजट की विशेषता जो केन्द्र सरकार के माननीय मंत्री राधामोहन जी ने अपने विभाग में रखा है कि एक डिमांड की फोरकास्टिंग कि आने वाले समय में किन उत्पादनों का डिमांड आयेगा, उसकी फोरकास्टिंग की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि किसान उसका सही समय पर उपयोग कर सकें ।

... क्रमशः ....

टर्न-7/आजाद/07.03.2018

..... क्रमशः ....

श्री मनोज कुमार : सबसे बड़ी बात है कि एक ग्राम के नाम से ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट की व्यवस्था की गई है, जिसका सर्वाधिक लाभ वैसे किसानों को मिलने जा रहा है । हमारी बिहार की सरकार ने भी जो कृषि रोड मैप में सहकारिता के क्षेत्र में त्रिस्तरीय विपणन व्यवस्था जो सब्जी उत्पादक हैं, आलू, प्याज यह सब जो सालों भर बिकने वाली सब्जियां हैं, आज तक किसी सरकारों ने इसके बारे में नहीं सोचा था । आज एक ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया और ऑपरेशन ग्रीन चलाने के साथ-साथ में जब हमारी राज्य की सरकार ने इस क्षेत्र में सहकारी कम्पनी बनाकर त्रिस्तरीय एक उत्पादन की, एक विपणन करने की और एक वितरण करने की और एक फेडरेशन के माध्यम से जो कार्य करने का प्रयास कर रही है, वह निश्चित तौर पर बड़े ही शुभकारी परिणाम आने वाले हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी दूरदर्शिता को, मंत्री महोदय की दूरदर्शिता को और हमारी सरकार का जो निर्णय है, हमारी सरकार की जो सोच है, मैं कई ऐसी बातें रखना चाहूँगा । जैसे इसमें सबसे बड़ी बात इस बजट की विशेषता है मोडल लैंड लाईसेंस कल्टीवेटर्स एक्ट, इस बार जो एक्ट लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें आज तक हमलोग यह बात करते थे कि जो रैयती जमीन लेकर खेती करते हैं, जो बटाई पर जमीन लेकर खेती करते हैं, जो लीज पर जमीन लेकर खेती करते हैं, उनके लिए भी यह एक्ट बनाने का कार्य किया गया है । अब इस एक्ट के माध्यम से सारे इन्स्टीच्यूशंस लोन, चाहे संस्थागत हो, चाहे जो भी अनुदान हो या चाहे जो भी सुविधायें हों, अब उन किसानों को भी मिल पायेगी, जो खेती कर रहे हैं लेकिन जिनके पास अपनी जमीन नहीं है । मैं चाहूँगा कि आप धन्यवाद इस बात का दें कि इस तरह का एक्ट लाने का कार्य यह सरकार कर रही है और आर्गेनिक फार्मिंग का जो हमलोगों ने जो लक्ष्य रखा था, 2016 में मैं कृषि विभाग के बजट पर बोल रहा था, विपक्ष के हैसियत से बोल रहा था, उस समय हमने कहा था कि आप जैविक खेती के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जैविक खेती के बारे में आपके पास कोई स्पष्ट निर्णय नहीं है । आज मुझे यह बताते हुए बड़ी हर्ष हो रही है कि

जब मैंने कृषि रोड मैप में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने का जो सरकार का कार्यक्रम देखा । पिछले साल लगभग मात्र 2हजार एकड़ में जैविक खेती करने का राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा था और इस वित्तीय वर्ष में उसे 25हजार एकड़ में करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है और जैविक खेती के लिए कॉरीडोर का भी चयन कर दिया गया है । अब अगले पॉच सालों में राज्य की सरकार यह कृतसंकल्पित है कि हम जैविक खेती को 50हजार एकड़ में करने जा रहे हैं । अब बताईए, आप कैसे बोलेते हैं भोला जी , रामानुज जी ने कहा कि आपका बजट लेआऊट 100 करोड़ रू0 कम है । ठीक है, 100 करोड़ बजट में हमने कम पेश किया है लेकिन आप अन्य राज्यों का उदाहरण देते हैं कि 18 राज्यों से आपका बजट का लेआऊट काफी कम है । मैं भी मानता हूँ कि हमने 1.6, 1.8 या 2 प्रतिशत के आस-पास का हमारा कृषि बजट है लेकिन कृषि बजट को देखने से काम नहीं होगा । आपको 1 लाख 54 हजार करोड़ रू0 का पॉच सालों का जो कृषि रोड मैप है, उसे देखना होगा और अगर उससे आप पॉच सालों से भाग देंगे तो लगभग 25हजार करोड़ से ज्यादा हम प्रतिवर्ष कृषि रोड मैप के माध्यम से खर्च करने जा रहे हैं ।

श्री भोला यादव : सभापति महोदय, किसानों के लिए सरकार को बजट बढ़ाना चाहिए लेकिन बजट कम किया गया है, यह कौन सी सरकार है ?

श्री मनोज कुमार : सभापति महोदय, मैं केवल एक बात बोलना चाहूँगा कि :-

हमको दुश्मन की निगाहों से नहीं देखा कीजिए,
प्यार ही प्यार है, हमपर भरोसा कीजिए ।

आप कृषि बजट को देखिए, कृषि रोड मैप को देखिए, 1 लाख 54 हजार करोड़ रू0 का यह कृषि रोड मैप है, 12 विभागों का मिलाकर के यह बनाया गया है । जैसे आज हम समेकित कृषि की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि इन्ट्रीग्रेटेड फार्मिंग हो, जब तक 12 विभागों का इन्ट्रीग्रेटेड एक्शन खेती के क्षेत्र में नही होगा, तब तक कृषि का विकास नहीं हो सकता है । कृषि के विकास के लिए सिंचाई भी चाहिए, कृषि के विकास के लिए सड़क भी चाहिए, कृषि के विकास के लिए माइक्रो एग्रीकल्चर भी चाहिए, कृषि के विकास के लिए कॉपरेटिव भी चाहिए, कृषि के विकास के लिए हाईवे भी चाहिए और यह बातें आपको समझनी होगी, इन बातों को आपको समझना होगा । साथियों, सभापति महोदय, मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा, मुझे इनके बातों पर एक शायर फिर याद आ रहा है :-

वो बेख्याल मुसाफिर, हम रास्ता यारो,
कहां था मेरे पास में, इनको रोकना यारो ।

आप तो बेख्याल मुसाफिर हैं, कोई लक्ष्य आपने नहीं रखा है, बेख्याल मुसाफिर की तरह चले जा रहे हैं और आप टोका-टोकी कर रहे हैं । मैंने कहा कि प्यार ही प्यार है, हमपर भरोसा कीजिए । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि इन बातों को अगर देखा जाय और इन बातों पर अगर उसे आत्मसात करने की कोशिश की जाय तो एक विपक्ष की भी सकारात्मक भूमिका के साथ में हम बिहार को काफी आगे लेकर जा सकते हैं । अब जैविक खेती के बारे में, सहकारी खेती के बारे में अब मैं आना चाहता हूँ कि अब हमारी राज्य की सरकार क्या-क्या कर रही है ? अब राज्य की सरकार को देखियेगा तो हमलोगों ने एक-एक

जिला में हमारे सभी विधायक इस बात से परिचित होंगे कि एक-एक जिला में कृषि विज्ञान केन्द्र खुला है, आत्मा का संचालन किया जा रहा है, उद्यान विभाग का संचालन किया जा रहा है, पौधा संरक्षण का काम किया जा रहा है, भूमि संरक्षण का काम किया जा रहा है । हम इससे अधिक प्रतिबद्धता क्या दिखा सकते हैं । पूरी व्यवस्था को सुधारने में आप एक दिन में कोई व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता है, पूरी व्यवस्था को सुधारने में लगातार सतत् प्रयत्नशील रहना पड़ता है और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आज जो यह सरकार है, जो पूरे इरादे के साथ में और पूरे चुनौती के रूप में यह बात बोल रही है, जिसका सबसे अधिक अगर पूर्ण नहीं होगा तो खमियाजा इसी सरकार को भुगतना पड़ेगा लेकिन हम इस पूरे संकल्प के साथ चूँकि हम अपने संकल्प को किसी भी परिस्थिति में बदलना जानते हैं । हमलोगों ने किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगुना करने का प्रण लेकर कहा है तो हमारा सारा लेआऊट, हमारी सारी करनी और हमारी सारी कथनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा । आप 2022 तक केवल हमारे कार्यों का समर्थन करते रहें और 2022 में जब हम असफल होंगे तब आप उस समय टोका-टोकी कीजियेगा ।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ , आपे डिजल अनुदान एवं बीज के बारे में बोल रहे थे । बीज का अनुदान और इससे कई कार्य जो किसानों को डायरेक्ट दिया जाता है, चाहे कृषि यंत्र मेला की बात हो, डॉ0 रामानुज जी बोल रहे थे कि कृषि यंत्र मेला कोई पटना में लगा देते हैं । कृषि यंत्र मेला में मैं कई अनुमंडलों में माननीय मंत्री जी के साथ में शिरकत किया हूँ । मैं देखा हूँ कि वहां पर कई किसानों का जमावरा लगा रहता है और कृषि यंत्र मेला का सर्वाधिक लाभ किसान लेते हैं । अब डिजल अनुदान की जो खमियां थी, उसे भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है । एच0डी0एफ0सी0 बैंक से मुझे जो जानकारी है, शायद मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता लेकिन एच0डी0एफ0सी0 बैंक से कृषि विभाग का कोई एग्रीमेंट होने वाला है, जिसमें डिजल अनुदान का पैसा एच0डी0एफ0सी0 बैंक के खाते में रहेगा और किसानों का जो एडवाईज नोट कटेगा, किसानों को डायरेक्ट डी0बी0टी0 कर दिया जायेगा । बीज के बारे में बता देता हूँ, उसका भी अब ट्रेजरी के साथ लिंक किया जा रहा है। किसानों को आई0एफ0एस0सी0 कोड और बैंक खाते के साथ उसको लिंक किया जा रहा है और साथ-साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माननीय नेता श्री प्रेम कुमार जी का, माननीय नेता नीतीश कुमार जी का, माननीय नेता राधा मोहन सिंह जी का, माननीय नेता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी का कि आपने किसानों के लिए जो कार्य किया है, आपने किसानों के वास्तविक जीवन स्तर को उठाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, बिहार और भारत प्रदेश का 70 सालों का पर्लियामेंट और मैंने देखा है कि क्या किया गया है किसानों के लिए, नारों के अलावा किसानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया है लेकिन आज सरकार कृतसंकल्प होकर के संकल्प के साथ किसानों के साथ में खड़ी है । आपको समर्थन देना होगा, आप चाहे अपने बाहरी मन से समर्थन नहीं दें लेकिन अन्तरआत्मा आपकी जरूर बोलती है कि अबकी बार किसानों के लिए कुछ न कुछ जरूर होकर रहेगा । किसानों का स्तर जरूर सुधरेगा और मैं कुछ बातों पर और ध्यान दिलाना चाहूँगा । जैसे कई समेकित प्रयास किये जा रहे हैं किसानों के जीवन स्तर को उठाने के लिए और कई इलाकों में समेकित खेती को

बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है । मेरा आग्रह होगा सरकार से कि इसे और पुष्ट करने की जरूरत है, इसमें और प्रयास करने की जरूरत है । समेकित कृषि के माध्यम से हम कई इलाके में मॉडल लगा सकते हैं, हमारे क्षेत्र में भी एक किसान समेकित खेती कर रहा है । मैं चाहूँगा कि लगभग हर पंचायत में ऐसे-ऐसे किसानों को ढूँढ़ा जा सके, जिससे इन्ट्रीग्रेटेड फार्मिंग कराया जा सके । इन्ट्रीग्रेटेड फार्मिंग की व्यवस्था हो, इसमें ऐसी व्यवस्था है कि हमारा हर उत्पाद किसी न किसी फार्मिंग के काम में आता है । इसके साथ-साथ में जो आपलोगों ने उद्यान, बागवानी मिशन का जो लक्ष्य रखा है - केला के लिए, अमरूद के लिए, पपिता के लिए, इसका भी सर्वाधिक लाभ हमलोगों को उठाना है और सबसे अधिक जो मत्स्यपालन के क्षेत्र में जो क्रांति होने जा रही है और इस पूरे चेन के माध्यम से, मेरा आग्रह होगा कि कृषि रोड मैप में मत्स्य के लिए कॉपरेटिव या कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि हमलोग मत्स्य उत्पादन के मामले में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो सकें और इन बातों के साथ में मैं पुनः माननीय नेता श्री प्रेम कुमार जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हुए कि आपने बेहतरीन बजट पेश करने का कार्य किया है, आपने कृषि रोप मैप बनाने का कार्य किया है । इसके लिए आपको बहुत,बहुत धन्यवाद और विपक्ष के साथियों से यह आग्रह करने के साथ में कि आपका कटौती प्रस्ताव जायज नहीं है, इसे आप स्वतः वापस ले लीजिए ताकि बिहार के किसानों में एक अच्छा संदेश जा सके, देश के किसानों में एक अच्छा संदेश जा सके कि बिहार की भी विधायिका काफी संवेदनशील है, बिहार का विपक्ष भी काफी संवेदनशील है और किसानों का हित को सोचता है, किसानों के साथ में संवेदनशीलता का भाव रखता है, इसी आग्रह के साथ कि आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें, आपने हमें बोलने का मौका दिया सभापति महोदय, बहुत,बहुत धन्यवाद ।

......

टर्न-8/अंजनी/दि0 07.03.2018

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री विनय वर्मा जी ।

श्री विनय वर्मा : सभापति महोदय, कृषि विभाग का एक अंग है गन्ना विभाग, उस पर मैं बोलना चाह रहा हूँ । हमारे प्रांत में अभी लगभग दो ही तरह की इन्डस्ट्रीज बच गयी है, एक होटल इन्डस्ट्री है और दूसरा गन्ना इन्डस्ट्री है । मैं चम्पारण से आता हूँ और चम्पारण में अभी हमलोगों के यहां गन्ने के मिलें वहां बची हुई हैं- पूर्वी, पश्चिमी चम्पारण मिलाकर 8 मिलें हुआ करती थी, अभी पांच मिलें वहां पर चल रही है । लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है । गन्ना कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसे कैश क्रोप कहते हैं । आप अगर कोई भी चीज धान, गेहूँ या मक्का कुछ भी लगाते हैं तो उसमें उतना रिटर्न नहीं आता है, जितना गन्ना का फसल लगाने से आता है । परन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां 80 परसेंट लोग गन्ने की खेती करते हैं और 20 परसेंट लोग धान, गेहूँ या अन्य फसल की खेती करते हैं । लेकिन सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा गन्ने की खेती करने वालों को, उन किसानों को बहुत ही बुरी नजर से या खराब नजर से देखा जा रहा है । अभी की हालत यह है कि सरकार ने गन्ने के किस्म के अलग-अलग रेट फिक्स किये- एक नम्बर

गन्ना का अलग रेट, दो नम्बर गन्ना का अलग रेट, तीन नम्बर गन्ना का अलग रेट, हर मिल का एक प्रेफेरी एक अपना एरिया होता है, जिसे उसे रिजर्व एरिया कहा जाता है । रिजर्व एरिया से चीनी मिल बाउंडेड है कि वह रिजर्व एरिया का गन्ना अपने मिल मे ले लेकिन अभी परिस्थिति यह चल रही है कि चीनी मिल के मालिकों द्वारा या उनके व्यवस्थापकों द्वारा रिजर्व एरिया का गन्ना नहीं लेकर पोचिंग किया जाता है यानी फ्री एरिया का जो गन्ना है, उसको लिया जा रहा है और रिजर्व एरिया के लगभग 40 हजार गन्ना किसान मुंह बाये बैठे हैं और आज तीन महीना मिल चलते हो गया । सरकार का उसपर कोई कंट्रोल नहीं है । अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो फ्री एरिया का गन्ना है, जो मिल वाले खरीदते हैं, वे कम दाम देकर खरीदते हैं । अगर 300 रूपये क्विंटल गन्ना है तो उसको 200-250 रूपये क्विंटल में खरीदते हैं । उस किसान की मजबूरी है कि वह फ्री एरिया का गन्ना दे ।

(व्यवधान)

श्री मो0 नेमतुल्लाह : माननीय गन्ना मंत्री जी पीछे बैठे हुए हैं, उनको आगे की बेंच पर बैठना चाहिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री :आप चाहते हैं कि गन्ना मंत्री जी फ्रंट पर आ जायें तो फ्रंट पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, माननीय मंत्री जी आ जायें ।

श्री भोला यादव : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इसपर ध्यान देना चाहिए ।

श्री विनय वर्मा : महोदय, मुझे यह कहना है कि अभी बात हो रही थी कि गन्ना मंत्री जी को फ्रंट में आना चाहिए, सरकार का गन्ना विभाग ऐसा है, उसके मंत्री हों या उसके पदाधिकारी हों, सबसे कमजोर आदमी को बनाया जाता है । 10 मिल-5 मिल इनलोगों के कंट्रोल में नहीं है । मुझे यह भी पता है कि क्यों नहीं रिजर्व एरिया का गन्ना आप उठने दे रहे हैं । मुझे यह भी पता है कि आप क्यों फ्री एरिया का गन्ना ले रहे हैं । आप भी उसी जिला के हैं, मैं भी उसी जिला का हूँ । मैं एक कठ्ठा भी गन्ना की खेती नहीं करता हूँ, आप करते हैं माननीय मंत्री जी । मुझे यह भी कहना है कि इन गन्नों को खरीदने वास्ते एरिया के लोगों को चालान निर्गत किया जाता है । आप इसकी जांच करा सकते हैं कि रिजर्व एरिया वाले लोगों को कितना चालान दिया गया और फ्री एरिया वाले लोगों को कितना चालान दिया गया है । आज कल कम्प्यूटराइज युग है, कम्प्यूटर में सब फीड किया हुआ है और सबके मोबाइल पर इसका आता है । मैं चाहूंगा कि इस पर जांच हो कि आपने क्यों नहीं रिजर्व एरिया के लोगों का गन्ना लिया ?

(व्यवधान)

जांच हो जायेगा तो वे भी उसमें फंस जायेंगे, इसलिए उनको नहीं रखा गया है बजट में आपने गन्ना के लिए क्या दिया है ? आप बतायें कि गन्ना के लिए आपने क्या दिया है ? क्या आपने महाराष्ट्र से बीज मंगाया है । (व्यवधान) हम सदन को ही न बता रहे हैं । आपको आगे बैठा दिया गया है बोलने के लिए नहीं, आप पीछे ही ठीक थे । यहां मिल की धांधली किस तरह से चल रही है, कांटा जो होता है, जिसपर गन्ना तौला जाता है, एक बैलगाड़ी से पांच किलो से सात किलो, एक टेलर से 10 किलो से 15 किलो, मैं पूछना चाहता हूँ विभाग से, क्या इसपर कभी किसी पदाधिकारी ने मिल के उपर एफ0आई0आर0

किया है क्यों नहीं किया है ? जनता रो रही है, किसान मारे जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है । मेरा एरिया ऐसा है कि जहां पर ओले पड़े, आज तक कृषि विभाग द्वारा या किसी विभाग द्वारा किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया । ओले में किसानों का गेहूँ बर्बाद हो गया, फिर उसके बाद बाढ़ आयी, बाढ़ आने पर धान का फसल नुकसान हो गया, मिल वालों ने अपनी मिल का पानी जो छोड़ा, उससे हजारों-हजार एकड़ गन्ना उससे सूखकर जल गया, उनके उपर कोई ध्यान नहीं दिया गया । आज किसी के घर में शादी है, किसी का लड़का पढ़ने जाता है, कोई मरा है, सब को पैसे की जरूरत है लेकिन त्राहि-त्राहि मचा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है । कितने पुतले फुंके जा रहे हैं लेकिन उसकी सुनवाई या उसका असर सरकार के पास नजर आती है ? मैं कहना चाहता हूँ कि तीन महीने मिल चलते हुए हो गये, आज वहां पर लोग त्रस्त हैं । कोई उनको सुनने वाला, देखनेवाला नहीं है । मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं सदन से अपील करता हूँ कि एक कमिटी बनाकर चलकर उसको देखा जाय कि किस हालत में हमारे किसान मर रहे हैं । उनको सुनवाई करनेवाला कोई नहीं है । एक सर्वे कराया गया है गन्ना विभाग द्वारा, हमारे चीनी मिलों द्वारा, बताइए सरकार को यह नहीं लगा कि कितना मेरा गन्ना नुकसान हुआ है, उस बी0डी0ओ0 को नहीं लगा कि मेरे क्षेत्र में कितना गन्ना नुकसान हुआ है, उसके फसल का हम सर्वे करा लें । आज चीनी मिलों ने खुद सर्वे कराया और करोड़ों रूपया बांटने के लिए गया है । मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि वह किसानों के हाथ में नहीं जायेगा, वह जायेगा मिल के पॉकेट में क्योंकि मिल वालों ने नकली लोगों का सूची बनाया है । हमारे मंत्री महोदय जो हैं, जब सबसिडी आया है तो इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को सबसिडी बंटवा दिया और बाकी जितने लोग हैं, जितने गन्ना खेती करनेवाले लोग हैं, आज तक इन्तजार करते रहे कि मुझे भी गन्ने का कुछ सबसिडी मिल जाय लेकिन नहीं मिला । मैं किसान हूँ, मेरा नुकसान हुआ है और इन्होंने आज से छः महीना पहले- आठ महीना पहले सबसिडी बंटवा दिया । मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि गन्ने के साथ-साथ सिंचाई विभाग को भी दुरूस्त करना पड़ेगा चूंकि पानी गन्ना के लिए बहुत ही आवश्यक है । केनाल टूटे हुए हैं, हमारे यहां त्रिवेणी केनाल है, त्रिवेणी केनाल टूटे हुए हैं और मैं यह सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि यथाशीघ्र उनकी मरम्मती करायी जाय । कुछ का टेंडर हो गया है, कुछ का बाकी है, कुछ ऐसे काम कराया जा रहा है, यही मंत्री महोदय ने उस काम को रोकवा दिया था । हमारे गन्ना के मिनिस्टर हों या जो भी हों, उनके बस की चीज नहीं है, सब की मिलीभगत है । गन्ना विभाग इन लोगों के कंट्रोल में नहीं है । वह फाइव स्टार होटल है, ये लोग जाते हैं, खुब अपना आनन्द उठाते हैं लेकिन मिल के खिलाफ में एक शब्द नहीं बोलते हैं । सब लोग पेरोल पर हैं । मैं कहना चाहता हूँ कि सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल के दाम, खाद के दाम, दवाईयों के दाम आसमान छू रहे हैं, आज गन्ना के किसान मजबूर होकर लेबर बनकर दूसरे-दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं और खेती उसी तरह से पड़ी रह जा रही है । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वे लोग इन्सान नहीं हैं, आप एग्रीकल्चर ऑफिसर को देखिए, कोई भी सबसिडी हो, कोई भी बात हो, उसके लिए बिना पैसा लिये हुए किसी को कुछ नहीं देता है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें ।

टर्न-9/शंभु/07.03.18

श्री विनय वर्मा : एक मिनट सर, कृषि विभाग से कोई मदद नहीं मिलती है । मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार किसानों के लिए क्या सोच रही है ? मैं चम्पारण से आता हूँ उस जगह से आता हूँ जहां महात्मा गांधी गये थे और नील की खेती करनेवाले जिनको निलहे कहते थे- निलहों पर अत्याचार से चम्पारण को और इस देश को मुक्त कराया । आज हमलोग मिल वालों के अत्याचार से दबे हुए हैं। सरकार से मेरा आग्रह है कि मिलों के अत्याचार से किसानों को मुक्त करायें, धन्यवाद ।

श्री विजय प्रकाश : सभापति महोदय, आज मैं वित्तीय वर्ष 2018-19 अनुदान मांगों के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं सदन के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे बोलने का मौका दिया गया इस सदन में। साथ-साथ मैं उस महान नेता को भी सादर सम्मान के साथ बोलना चाहता हूँ जिन्होंने इस सदन में पहुंचाने का काम किया आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी, जिन्होंने इस सदन में हमलोगों को बोलने के लिए मौका उनके आशीर्वाद से मिला । आज ग्राफ बढ़ाने वाले तो ग्राफ बढ़ाने में खुद लगे रहेंगे । आज सदन में कृषि के सवालों पर कटौती प्रस्ताव और उसके अनुदानों के विरोध में बोलना है । सबसे पहले बिहार और भारतवर्ष को कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है और है भी । बिहार की संपूर्ण आबादी देश की संपूर्ण आबादी कृषि पर निर्भर करता है और इस देश के महान नेता हमलोगों के स्व0 चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के महान नेता थे। उनके साथ हमारे सामने में बैठे हुए संसदीय कार्य मंत्री श्रवण बाबू भी काम कर चुके हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम कर चुके हैं, लेकिन आज किसानों के प्रति और कृषि के प्रति क्या भावना है, उस भावना से दूर जाकर स्व0 चौधरी चरण सिंह के सपनों को चूर-चूर करके आज भारतीय जनता पार्टी और आर0एस0एस0 के गोद में जाकर बैठने का काम किया गया है । बिहार के नेता हमारे किसान के नेता सहजानन्द सरस्वती जी, जिन्होंने कृषि को कैसे आगे बढ़ाना है, किसानों के सम्मान और प्रतिष्ठा को कैसे आगे बढ़े, कैसे खुशहाल हो इसकी चिंता सहजानन्द सरस्वती जी किया करते थे । आज श्री चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश के समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है । यह मुस्कान हमलोगों को यह देखना है कि कैसे बिहार में जो कृषि को उन्नत होना था वह आज दिन प्रति दिन गिरावट की ओर जा रहा है । हमें यह सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ रहा है, विवश होना पड़ रहा है कि बिहार में किसानों के साथ और कृषि की जो दुर्दशा हुई है इसपर हमें चिंता करना जरूरी है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते है। सदन में बैठे हुए माननीय मंत्री जी तो चले गये हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि पहला कृषि रोड मैप का क्या हश्र हुआ, दूसरा कृषि रोड मैप का क्या हश्र हुआ उसकी तो चर्चा करते तब आप तीसरे कृषि रोड मैप का- आपने जिस तरह से आडंबर फैलाकर पूरे देश में प्रेस और मीडिया के माध्यम से जागृति फैलाकर महामहिम राष्ट्रपति जी को लाकर कृषि रोड मैप का तीसरा शुरूआत किया, उसका आज क्या हश्र है ? तीसरा कृषि रोड मैप शुरू करने के पहले जो एक और दो नंबर के रोड मैप थे उनमें क्या कमी हुआ, कहां तक आप सक्सेस किये इसकी भी चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं । जिस तरह से हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी चार साल में

चार-चार बार कभी इनके साथ गलबहियां करके, कभी उनके साथ गलबहियां करके सरकार और कुर्सी से जो चिपक जाते हैं, ठीक उसी तरह से कृषि रोड मैप को भी आडंबर फैलाकर इसको दिग्भ्रमित करने का काम किया । आज पूरे बिहार में कहीं भी जाइये, आज क्या स्थिति है बीज का वितरण क्यों नहीं हो रहा है ? इसमें क्यों घपलाबाजी शुरूआत हुआ है ? इसकी क्या स्थिति है । आज क्या कारण है कि लोग गरीब त्राहिमाम में हैं । किसी को बीज नहीं मिल रहा है, किसी को खाद नहीं मिल रहा है, सभी जगह किसान मर्माहत पड़े हुए हैं । अभी भी आप तो हमारे बगल के हैं विजय जी कम से कम जिस जिला में हमारा जन्म हुआ है, उसी जिले के आप हैं, भले ही हम जमुई जिला अपने ननिहाल में रहते हों । आप वहीं के हैं आपको मालूम होगा कि आप दवा का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हमलोग किसान और खेत में मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं । एकदम खेती किये हैं आप जाकर पता कर सकते हैं । इसलिए आज जो स्थिति है बिहार में आज इसकी चर्चा हमलोगों को करना पड़ेगा । किसान आज कर्ज में डूबा हुआ है, किसान को ऋण मुहैय्या नहीं हो रहा है । यदि किसी तरह से किसानों को ऋण मुहैय्या हो रहा है तो उनपर लादा जा रहा है और दौड़ते रह जाते हैं बैंकों में उन्हें नहीं मिलता है । गोदाम की स्थिति बद से बदतर है । आप किसानों के आज हम बता रहे हैं दावे के साथ कि जितना भी किसानों ने धान का उपज किया है- क्या सबों की खरीद हो चुकी है ? सभी बाजार में बेचने का काम किया है, लेकिन आज पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं कि सभी बाजार से सरकार के पास आ चुका है । यह नारा लगाने में और अच्छे-अच्छे शब्दों में बोलने में आपलोग थोड़ा सा माहिर पड़ते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस जुमलाबाजी के साथ जो आदत आपको लगाया है, उसके मनुवादी व्यवस्था के साथ आप उनके साथ आकर्षित होकर गलबहियां करके उनके शब्दों का प्रयोग करने में मीठे-मीठे शब्दों का प्रयोग करने में आप भी थोड़ा माहिर हो चुके हैं । यह दुर्भाग्य है कि महागठबंधन की सरकार, जिसमें सात निश्चय के माध्यम से जो आपको जनमत मिला था जिस जनमत का अनादर करके हमें यह कहने में गुरेज नहीं है । यदि माननीय मुख्यमंत्री जी रहते तो बड़े हश्र के साथ आपके साथ लालायित होकर लोगों ने लगातार एक कट्टरपंथी को हटाना है, बिहार में धर्म निरपेक्षता का सरकार बनाना है और उसका अनादर करके आपने उन सपनों को 11 करोड़ मतदाता मालिकों के सपनों को चूर करके उनके सपनों को लात से कुचलकर आप भारतीय जनता पार्टी और आर0एस0एस0 कट्टरपंथियों के साथ गलबहियां करके आज सात निश्चय जो सात निश्चय की चर्चा होती है वह सात निश्चय किसका है- आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का । आज क्या कारण है कि आज आपके साथ एक भी काम नहीं हो पाया है । आपका आदत खराब हो चुका है । आपलोग हमेशा शिकारी की तरह काम करते हैं ।

क्रमशः

टर्न-10/अशोक/07.03.2018

श्री विजय प्रकाश : क्रमशः... शिकारी की तरह काम करते हैं । हमेशा शिकारी की तरह काम करते हैं । शिकारी आयेगा, जाल बिछायेगा, दाना डालेगा । जाल बिछायेगा और वह भारतीय जनता पार्टी बड़े जुमलेबाजी शब्दों में माननीय नीतीश कुमार जी पर अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सपना

दिखाकर और जो हैं सृजन घोटाला के मामले को दिखाकर के इनको जाल में फंसा कर आप उनको अपने कब्जे में कर लेने का काम किया है । यह दुर्भाग्य है कि आपने जो अच्छे सपनों को दिखाया, उस सपनों को तार-तार करने का काम किया है । आज अच्छे दिन के बाद करते हैं, कहां गया मेक इन इन्डिया ? क्यों आप नहीं भूल पा रहे हैं, मूल बातों से आप अलग क्यों हो चुके हैं । कहां गया जमीन का हेल्थ कार्ड ? क्या हुआ ? कहां गया ? विशेष पैकेज ? विशेष राज्य का दर्जा आज आप सपना में जो है उनके साथ मेल हो गये, सपना दिखलाया गया है लेकिन आज जो है कृषि रोड मैप कहां गया, विशेष पैकेज कहां गया ? कहां गया मेरा विशेष राज्य का दर्जा ? क्या हुआ ? कृषि विभाग को? विशेष राज्य के दर्जा के अनुसार कृषि विभाग को क्या मिला ? विशेष पैकेज क्या मिला है ? यह माननीय मंत्री जी बतलाने का काम करें । कहां है बीज ? बीज के उत्पादन की क्या स्थिति है ? अभी माननीय कुशवाहा जी बोल रहे थ, हम हंस रहे थे उन्होंने बोला कि अच्छे अच्छे कम्पनियों के माध्यम से हम बीज मुहैया करा रहे हैं और अच्छे फसलों का प्रयोग है, आज मैं आपलोगों को सदन में दिखलना चाहत हैं यह मक्का का फोटो हैं, (फोटो दिखलाते हुये) इसको देख लिया जाय कितना लम्बा मक्का, बाउन्ड्री जितना लम्बा मक्का हो गया है लेकिन दाना एक भी नहीं है, यह आज का है, आप ही के कृषि विभाग का है । कहां कृषि मंत्री महोदय, जरा इसको दखेंने काम काम करें, आखिर कौन इसको देंखेगे, कौन इसकी चर्चा करेंगे ? कौन किसानों के साथ छल कर रहे हैं? यदि बिहार की मिट्टी में क्या दम है, क्या गुण है और आप तमिलनाडू से लाइयेगा, आप गुजरात से लाइयेगा, क्योंकि गुजरात आज के तारीख में आपको बहुत प्रेम हो गया हैं । गुजरात में एक समय ऐसा था माननीय मुख्यमंत्री जी आप से जब कोई हाथ मिला लेता था तो हाथ खींच लेते थे, वह दिन मुझको याद है । एक दिन ऐसा भी था कि माननीय मुख्यमंत्री और सुशील मोदी जी ने दिल्ली के एक मिटिंग में गये थे और भारतीय जनता पार्टी के होने वाले प्रधान मंत्री जो सपना देख रहे थे और आज वर्त्तमान में प्रधानमंत्री हैं । वे ताकते रह गये कि हमसे हाथ मिलायेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और सुशील मोदी जी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी जी रहते हुये उनके रास्ता से अलग कट कर के, जैसे बिलाई रास्ता काट देता है उस तररह से निकल कर, नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी निकल गये थे । उन्हीं का गुण गा रहे है, आज किनका गुण गा रहे हैं ? एक तरफ चुम्मा भी देते है और दूसरी तरफ थप्पड़ भी मारते हैं, एक दिन एक गाल में थप्पड़ मारते हैं और दूसरे गाल में चुम्मा भी देते हैं, यह दोहरी नीत नहीं चलेगी । बिहार में (व्यवधान)बोलने के लिए इतना है कि आप समझ ही नहीं पाइयेगा, बनावटी किसान आप लोग हैं, आज क्या कारण है कि कृषि विभाग में रास्ता पकड़े हैं ऐसा कि आपका छुट्टी, लीव हो जायेगा । आज कृषि विभाग में आप दिन प्रति दिन प्रत्येक साल अम्बार आप बजट का लगा रहे हैं जब कि कटौती इस बार की गई है, नहीं मालूम प्रेम कुमार जी से क्या गुस्सा है नीतीश कुमार जी को और खास करके वित्त मंत्री को क्या गुस्सा है ? कहीं हमसे आगे न बढ़ जायं । इसलिये इनके विभाग के बजट की कटौती कर दो और कटौती करने के बाद रोज प्रति दिन बजट बढ़ रहा है, लेकिन कितने आपके यहां जिला में कृषि पदाधिकारी हैं यह बतलाने का काम करें, कितने आपके अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी है ? कितने प्रखण्ड में कृषि पदाधिकारी हैं ? एक भी कंटिन्यू नहीं कर रहा है । पूरे बिहार में बद से बद्तर स्थिति है, आप हरएक टाईम किसान सलाहकार के बल पर चल

रहे हैं, यह दुर्भाग्य है, यह लानत है, आप प्राईवेट लोगों से विभाग को चलाना चाह रहे हैं, यह आपलोगों को देखना पड़ेगा ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय प्रकाश : और अंत में महोदय यह बतलाना चाहते हैं कि जरा कल ही चर्चा हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे, खुशी मना रहे थे और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बतलाया था कि कोई दारू लाकर दिखला दे, हम सदस्यता से खत्म हो जायेंगे । माननीय सुशील मोदी जी बोले, आप देख लीजिये कि एक स्कूल में शिक्षकों ने दारू पी-पी कर स्कूल के बच्चे, आपके सामने बोतल लेकर खड़ा है, यह देख लीजिये(फोटो दिखलाते हुये)। यह सहर्षा का मामला है, यह दुर्भाग्य है, यह आज का मामला है ।आज का है, यह देख लीजिये । कहां गई आपकी शराब की नीति जो बच्चे लेकर बैठे हुये स्कूल में, सहर्षा के स्कूल में,वहां ताला लगाया गया है और शिक्षक शराब पी रहे हैं यह देखिये । क्योंकि आज उत्पाद पर भी चर्चा है, उत्पाद विभाग का भी हैं, यह दुर्भाग्य है, आप लोगों पर लानत है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): आपका समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता जी ।

श्री विजय प्रकाश : महोदय, एक मिनट ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): नहीं, आपका समय समाप्त हो गया । माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता जी।

श्री विजय प्रकाश : एक मिनट, अपने क्षेत्र की बात है । बहुत खुशी की बात है, कृषि विभाग ने- पूरे बिहार में जो नहीं हो पाया है वह हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत, किसानों ने अपनी मेहनत से राज्य का नाम ऊंचा किया है । राज्य का नाम ऊंचा किया है, राज्य का नाम ऊंचा किया है जैविक गांव केड़िया, जीवित माटी किसान के तहत । जो अभी पूरे बिहार में नहीं हुआ है हम चाहते हैं कि कृषि विभाग के द्वारा जैविक हाऊस का निर्माण किया जाना चाहिए, कृषि विभाग के द्वारा ऑरगेनिक हाऊस का निर्माण होना चाहिए । क्योंकि पूरे बिहार में हम इसको दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस स्थिति से वह केड़िया गांव में चल रहा है वह कहीं नहीं है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता जी ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र के इस पवित्र सदन में वर्ष 2018-19 के व्यय विवरणी पर सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मॉग के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूॅं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आर्दिक आभार व्यक्त करता हूॅं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री महादेय का आभार व्यक्त करता हूॅं । मैं आभार व्यक्त करता हूॅं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय कृषि का एवं माननीय मंत्री महोदय संसदीय कार्य का भी आभार व्यक्त करता हूॅं ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं । हमारे नेता विकास पुरूष आम जनता के साथ जो वादा किया आज हरएक जिले, ग्राम पंचायत में कार्य दिख रहा है । सात निश्चय के तहत् हरएक कार्य को जमीन पर उतारने का काम किया है । आज दो वर्ष बीतने के दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2016 के दिसम्बर में निश्चय यात्रा तथा भीषण कड़ाके की ढंढ में दिसम्बर-जनवरी, 2017-18 में सभी 38 जिले की विकस समीक्षा यात्रा के साथ लोकार्पण कर सात निश्चय गली-नली योजना हो, हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, चाहे शैचालय का कार्य हो

सभी कार्य जमीन पर लागू कराने का काम किया है । आज कार्य हरएक ग्राम पंचायत में चल रहा है ।

महोदय, कृषि जिस विभाग पर बोलने के लिए मुझे समय मिला है । वर्ष 2017, राज्य में कृषि विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताओं का वर्ष रहा है । वर्ष 2005 के पहले कृषि विभाग में क्या कार्य होता था, सभी लोग तथा सभी माननीय सदस्य जानते होंगे कि 2005

श्री अवधेश कुमार सिंह : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । सभापति महोदय, कृषि बजट चल रहा है, कृषि बजट पर संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुये हैं, उनको बधाई है । न तो कृषि मंत्री बैठे हैं और न कृषि सचिव अधिकारी दीर्घा में बैठे हैं और गन्ना कमीश्नर भी नहीं हैं । सदन में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है । हमलोग सदन के पुराने सदस्य हैं, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, प्रश्न यह है कि कृषि बजट चल रहा है, कृषि मंत्री को बैठना चाहिए। बजट चल रहा है, कृषि विभाग के पदाधिकारी, प्रधान सचिव, सचिव को बैठना चाहिये और गन्ना कमीश्नर को बैठना चाहिये । और सदन की गरिमा है सभापति महोदय, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। क्रमशः...

टर्न-11/ज्योति/07-03-2018

क्रमशः

श्री अवधेश कुमार सिंह : इसके ऊपर आप नोटिस लें और सभापति महोदय, इसपर आवश्यक कार्रवाई करें।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, माननीय अवधेश बाबू बहुत सीनियर मेम्बर रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं । माननीय मंत्री यहाँ पर बैठे थे अभी गए हैं । माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसे सवाल को उठाया है, उसके समाधान के लिए उनके सचिव आए हुए हैं, अभी बाहर में बात करने के लिए गए हैं और गन्ना विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं । सदन में सरकार बैठी है और सदन में जो बातें आ रही हैं उसको एक एक करके नोट किया जा रहा है और माननीय मंत्री गन्ना उद्योग भी बैठे हुए हैं तो माननीय सदस्य बहुत सीनियर हैं और उनको सब बात की जानकारी है और उसके बाद भी इन सवालों को क्यों उठाते रहते हैं ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : सभापति महोदय, वर्ष 2005 के पहले कृषि विभाग में क्या कार्य होता था । सभी लोग थे, सभी माननीय सदस्य जानते होंगे कि 2005 के पहले हमारे किसान भाई कृषि विभाग संबंधी कुछ नहीं जानते थे कि कृषि विभाग से क्या लाभ मिलता है । 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिहार की शासन सत्ता की बागडोर संभाली तो सभी विभाग में विकास की नयी शुरुआत हुई और उसका शुभारम्भ किया गया । कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए पहला कृषि रोड मैप वर्ष 2008 में, दूसरा कृषि रोड मैप 2012 में और तीसरा कृषि रोड मैप दिनॉक 9 नवम्बर 2017 को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा शुभारम्भ किया गया । कृषि सहित 12 विभाग को शामिल करते हुए आगामी पॉच वर्षो के लिए 154.1 करोड़ की लागत से तीसरा कृषि रोड मैप का शुभारम्भ किया गया । महोदय, राज्य में 185.6 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का रेकर्ड उत्पादन हुआ है । मक्का उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए चुना गया । 1 करोड़ किसानों के बदौलत यह उपलब्धि हासिल हुई है । इस मैप के अधीन वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन तथा गोबर गैस

की स्थापना के लिए किसानों को सहायता राशि उपलब्ध करायी जा रही है । राज्य में जैविक उत्पादन को प्रमाणित करने के लिए बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण एजेन्सी की स्थापना की गयी है जिसका पहली बार किसानों का निबंधन शुरु कर दिया गया है। महोदय, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 22,172 पक्का वर्मी कम्पोस्ट के द्वारा तथा 160 गोबर गैस के निर्माण के लिए किसानों को सहायता दी गयी है । हरी खाद के लिए 63,692 क्वींटल ढैचा का बीज अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है । बीज उत्पादन तथा उसके उपयोग में गुणात्मक वृद्धि मुख्यमंत्री तीव्र विस्तार योजना, बीज वितरण योजना, बीज ग्राम योजना का कार्यान्वयन प्रमुखता से किया गया है । विभिन्न फसलों के 1 लाख 10 हजार क्वींटल से अधिक प्रमाणित बीज किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये गए हैं । इस वर्ष 24 हजार हेक्टेयर्स से अधिक क्षेत्र को बीज प्रमाणीकरण के लिए निबंधित किया गया है । बीज की गुणवता की जॉंच के लिए पटना में एक डी.एन.ए. जॉंच प्रयोगशाला भी स्थापित किया गया है । महोदय, राज्य में आधुनिक कृषि यंत्र को बढ़ावा देने के लिए 71 प्रकार के विशेष उपयोग के कृषि यंत्रों के लागत मूल्य का 50 प्रतिशत सरकारी सहायता उपलब्ध करायी जा रही है । अभी कोई कोई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कृषि यंत्र का कहीं कुछ नहीं है । 2005 से पहले कुछ नहीं था लेकिन 2005 के बाद जो किसानों को लाभ दिया गया है हरेक प्रखंड कार्यालय में उसका एडवर्टिजमेंट किया गया है । अभी प्रखंड में प्रखंड स्तर पर भी कृषि यांत्रिक मेला लगता है जिससे किसान को हरेक यंत्र लेने में वहॉं अनुदानित दर पर मिलता है । यह हमलोग अपनी आंख से देखें हैं और हम भी किसान हैं और हरेक मेला में हमलोग जिला तक जाते रहते हैं । महोदय, इस वर्ष 1 लाख 53 हजार किसानों के आवेदन पर 80 हजार किसानों को स्वीकृति पत्र दिया जा चुका है तथा 28 हजार से अधिक किसानों ने नये कृषि यंत्रों का क्रय कर लिया है । 3 हजार से अधिक कृषि समन्वयकों की स्थायी नियुक्ति की जा चुकी है । पंचायत स्तर पर किसान पाठशाला एवं कृषि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है । कृषि सलाहकार का मानदेय 8 हजार रुपया प्रति माह से बढ़ाकर 12 हजार रुपया प्रति माह किया गया है । राज्य में बागवानी विकास के लिए 1296 एकड़ में, आम 101 एकड़ में, लीची 101 एकड़ में, 47 एकड़ में अमरुद, 60 एकड़ में आंवला और 145 एकड़ में पपीता तथा 1390 एकड़ में केला के नये बगानों की स्थापना की गयी है ।

श्री विजय प्रकाश यादव : आप बोल रहे हैं स्थापना की गयी है धरातल पर कितना है ? वह बतला दीजिये ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय सदस्य सब धरातल पर हो रहा है । माननीय सदस्य जरा धैर्य रखा जाय। हरेक काम सरकार कर रही है ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : शांति बनाये रखें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय सदस्य सीनियर सदस्य हैं, धैर्य रखा जाय । मिट्टी जॉंच के आधार पर राज्य में किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं इस वर्ष 9 लाख 10 हजार किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड दिया गया है । पिछले तीन वर्ष में 55 हजार से अधिक किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया गया है । सभापति महोदय, गया, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर जिलों में 3 नये कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत

सरकार को जमीन उपलब्ध करायी गयी है । डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बिहार के छात्रों को 2500 रुपया प्रति माह स्टाईपेंड की भी स्वीकृति दी गयी है । महोदय, वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग द्वारा कुछ कार्यक्रम का व्योरा भी मैं निम्न प्रकार सुना रहा हूँ सदन को । आधुनिक प्रभेदों के बीज धान, गेहूँ के साथ साथ दलहन एवं तेलहन के आधुनिकत्तम बीज के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ाने के लिए बीज वाहन एवं विकास वाहन के माध्यम से किसानों तक कृषि तकनीक के साथ साथ आधुनिक बीज का विस्तार भी किया जायेगा । यह सरकार का प्रोग्राम है, यह विभाग का प्रोग्राम है । जैविक सभी खेती को बढ़ावा देने लिए इनपुट सब्सिडी योजना चलायी जायेगी । वर्मी कम्पोस्ट तथा जैव उर्वरक के प्रोत्साहन के साथ साथ गोबर गैस की स्थापना की भी योजना चलायी जायेगी ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें, आपका समय खत्म हो गया ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, दो मिनट । किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान राशि दी जायेगी । बागवानी के विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मीशन के साथ साथ मुख्यमंत्री बागवानी मीशन योजना चलायी जायेगी और जल छादन के आधार पर भी मिट्टी जल संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जायेगा किसानों की मिट्टी के जॉच के आधार पर स्वायल हेल्थ कार्ड दिए जायेंगे । महोदय, पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय भी स्थापित किया जायेगा ताकि किसानो को अपने ही पंचायत में सभी प्रकार के कृषि योजना की जानकारी प्राप्त हो सके । महोदय, कृषि के क्षेत्र में नाबार्ड की पद्धतियों को बढ़ावा दिया जायेगा । प्रगतिशील किसानों को भी पुरस्कृत किया जायेगा । कृषि योजनाओं का युक्तिकरण किया जायेगा तथा योजनाओं की संख्या कम की जायेगी । महोदय, किसानों की आमदनी को दुगुना करने के लिए इन्द्रधनुषी क्रांति के लिए समेकित कृषि प्रणाली पर बल दिया जायेगा तथा इसे अपनाने के लिए किसानों के प्रशिक्षण के साथ साथ आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी । मैं माननीय मंत्री महोदय से थोड़ा अपने क्षेत्रीय मांग का उल्लेख करुंगा और यह मांग जो है, यह जेनरल मांग भी हो सकती है । आज किसान अनाज पैदा करते हैं और उनको वाजिब रेट पर बाजार में उसको सही मूल्य नहीं मिल पाता है इसलिए मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ, मांग करता हूँ कि जैसे प्रखंड स्तरीय मंडी , पंचायत स्तरीय मंडी हो उनमें किसानों को उचित मूल्य मिले और किसान खुशी खुशी अपनी खेती करें । मैं माननीय मंत्री महोदय से इस सदन के माध्यम से मांग करता हूँ । अंत में महोदय, मैं पुन: सदन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय आपका, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आभार व्यक्त करता हूँ तथा पेश बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ । जयहिंद, जय बिहार, धन्यवाद ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : माननीय सदस्या श्रीमती अरुणा देवी ।

श्रीमती अरुणा देवी : सभापति महोदय, कृषि विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पेश 2747.77 करोड़ रुपये के बजट के लिए दिए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हूं। महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहॉं 75 प्रतिशत जनता गांव में निवास करती है तथा खेती पर ही निर्भर करती है । उनकी आजीविका का मुख्य साधन खेती है । यदि हमारे राज्य के किसान विकसित और शिक्षित नहीं होंगे तो इसका प्रतिकूल असर अनाज के उत्पादन पर पड़ेगा । क्रमश:

टर्न–12/07.3.2018/बिपिन

श्रीमती अरूणा देवी : (क्रमशः) कृषि रोड मैप के अलावे 11 अन्य विभागों यथा, जल संसाधन, ऊर्जा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य, पर्यावरण एवं गन्ना उद्योग को सम्मिलित कर बड़े–छोटे किसानों एवं मजदूरों के असंतोष एवं कठिनाइयों को दूर करके तकनीकी सहयोग के लिए समृद्धि लाने की कोशिश की गई है । खेतिहर मजदूरों के पोषण आय बढ़ाने एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण पर सरकार विशेष फोकस दे रही है। महोदय, राज्य के अधिकतर किसान प्रशिक्षित नहीं हैं । किसानों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने हेतु कृषि शिक्षा जरूरी है । इसके लिए गया में कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज, फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज, पटना में कृषि व्यावसायिक प्रबंधन कॉलेज एवं आरा में जैविक पौधिक कॉलेज की स्थापना का प्रावधान किया गया है । महोदय, पूर्वी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर जिले में तीन नए कृषि विज्ञान केंद्र, समस्तीपुर में राष्ट्रीय स्तर का फॉर्म, मशरूम ट्रेनिंग इंस्टीच्युट की स्थापना की जा रही है ।

महोदय, 2017–18 में 9–10 लाख किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड दिया गया है । अभी तक 55 लाख से अधिक किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया गया है । महोदय, खाद्यान्न में पोषण, उपभोक्ता का सेहत और किसानों की आमदनी के लिए सरकार ने सब्जी की खेती प्रोत्साहित करने की दिशा में भी अपना कदम बढ़ाया है । पटना से भागलपुर तक गंगा के किनारे तथा दनियावां से बिहार शरीफ तक राष्ट्रीय एवं राजकीय मार्गों के आसपास गांवों में जैविक कॉरीडोर विकसित किया जा रहा है । जैविक कॉरीडोर के तहत 300एकड़ जमीन पर जैविक सब्जी उपजाने हेतु 6000/– प्रति किसान अग्रिम अनुदान दिया जाएगा । यह योजना पायलॉट प्रोजेक्ट के रूप में नालन्दा, पटना, समस्तीपुर एवं वैशाली जिले में प्रायः किया जा रहा है । महोदय, सरकार द्वारा राज्य में बागवानी के विकास के लिए 1296 एकड़ में आम, 100 एकड़ में लीची, 47 एकड़ में अमरूद, 60 एकड़ में ऑवला, 145 एकड़ में पपीता, 13.90 एकड़ में केला के नए बागवानी की स्थापना की गई है । महोदय, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में पर्यावरण तकनीकी सहयोग करने हेतु लगभग 1300 कृषि समन्वयकों की स्थायी नियुक्ति की गई है । साथ–ही–साथ, संविदा पर नियोजित समन्वयकों को अनुदान में वृद्धि की गई है । महोदय, राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पक्का वर्मी कंपोस्ट तथा 107 गोबर गैस के निर्माण हेतु किसानों को सहायता दी गई है । हरी खाद के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु 6392 क्विंटल ढइंचा का बीज किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया गया है । महोदय, राज्य के किसानों को मात्र कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने शीघ्र ही केंद्रीय फर्म मशीनरी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सदन के द्वारा राज्य में शराबबंदी लागू करने का बेहतर परिणाम दिखाई दे रही है । आज शराब के चलते बर्बाद हुए परिवारों का जीवन शराबबंदी के चलते सुखमय हो गया है । शराबबंदी के लागू होने से राज्य में लूट, हत्या, सड़क दुर्घटना इत्यादि में काफी कमी आई है । आज सरकार शराबबंदी से प्रभावित होकर पुनः

नशामुक्ति की तरफ अपना कदम बढ़ा रही है । महोदय, शराबबंदी के कारण अपराध के मामले में काफी कमी आई है । फिरौती के लिए अपहरण, हत्या, डकैती जैसे मामलों 25 प्रतिशत् से अधिक कम हुए हैं । सड़क दुर्घटनाओं में भी लगभग 20 प्रतिशत् कमी आई है । दुग्ध उत्पाद की खपत भी बढ़ी है । शहद, पनीर जैसी वस्तुओं की खपत 200 से 400 परसेंट तक बढ़ी है । महोदय, मुख्यमंत्री नवाचार योजना के अंतर्गत सब्जी के उत्पादन, वितरण हेतु सहकारी समिति का गठन किया जा रहा है । महोदय, राज्य सरकार कृषि एवं मद्य निषेध के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है जिससे राज्य के किसानों एवं महिलाओं को विशेष लाभ पहुंच रहा है । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): माननीय सदस्य श्री मदन मोहन तिवारी जी ।

श्री मदन मोहन तिवारी: सभापित महोदय, मैं सरकार के द्वारा, सरकार के मंत्री के द्वारा, कृषि मंत्री के द्वारा लाए गए कृषि बजट पर कटौती प्रस्ताव जो लाया गया है, मैं उस कटौती के पक्ष में तथा सरकार के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं ।

सभापति महोदय, सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है और कृषि पर आधारित है । गांव के कृषि करने वाले लोगों के बारे में सरकार को अभी तक कोई संज्ञान नहीं है कि उनका क्या दुख है, क्या दर्द है, उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए । हमलोग गांव से आते हैं । गांव में सरकार के द्वारा ब्लॉक में रब्बी, खरीफ फसल के लिए बीज के लिए, उसके गुणवत्ता के लिए नामचीन लोगों को, हर गांव से नामचीन लोगों को बी.ए.ओ. के द्वारा, डी.ए.ओ. के द्वारा ब्लॉक में बुलाकर ठंडा पिला कर के मिठाई का पैकेट देकर और उनको बीज देती है । आम किसान से सरकार के किसी भी कर्मचारी का कोई मतलब नहीं है । जो गृहस्थी करता है उसके यहां इस शिविर का कोई खबर नहीं जाता है ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 2009 में जब भारत सरकार में यू.पी.ए. की सरकार थी तो उस सरकार ने 78 हजार करोड़ रूपया भारत के किसानों के लिए कर्ज माफी का काम किया था लेकिन चार साल में भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा कि उनका कर्ज कैसे जाएगा ? मैं चम्पारण से आता हूं सभापति महोदय, चार साल के अंदर में न भारत सरकार का, न बिहार सरकार का किसी तरह का फसल बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिला सरकार के कर्मचारियों के द्वारा । सरकार के यहां एप्लाई किया जाता है डेयरी के लिए, गाय के लिए, गाय के लिए सरकार अपने-अपने नुमाइंदों को स्वीकृत करके दे देती है लेकिन जब बैंक के पास वे जाते हैं तो बैंक का कहना होता है कि पुराना भुगतान सरकार नहीं किया है, इसलिए आपको सबसिडी पर लोन नहीं देंगे। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं सर कि सरकार पुराना भुगतान करे ताकि कम-से-कम नए गृहस्थ जो लोन लेकर डेयरी चलाना चाहते हैं उनका जीवन अच्छा तरीका से बीते । हम, महोदय, चम्पारण के बेतिया से आते हैं जहां किसानों की मुख्य गृहस्थी गन्ना है । प्रतिदिन रिजर्व के किसान मिल के पर्ची के लिए भटकते हैं । घटतोली के लिए थाना में जाते हैं, नेतागिरी करते हैं, सड़क जाम करते हैं लेकिन उपर तक जाते-जाते उनलोगों को कौन मैनेज

कर देता है, सरकार के मुलाजिम जाकर के मैनेज करके उनके बात को दबा देते हैं जिसके चलते टायर पर एक से दो क्विंटल, टेलर पर पांच से सात क्विंटल और ट्रक पर न जाने कितना क्विंटल बी.ए.ओ. के द्वारा घटतोली की जाती है लेकिन सरकार का इसपर कोई ध्यान नहीं है ... क्रमशः...

टर्न–13/कृष्ण/07.03.2018

श्री मदन मोहन तिवारी (क्रमशः) लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है । सभापति महोदय, बिहार के कई जिलों में नेपाल के रास्ते से पानी आया था, इसमें चार–पांच पंचायत सहित मेरे विधान सभा क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित हुआ था । बाढ़ में मैं लोगों के पास मिलने के लिये गया । सरकार के द्वारा घोषणा हुई थी कि जिसके घर में पानी घुसा होगा, उसको 6 हजार रूपया दिया जायेगा और जिसकी फसल की क्षति हुई होगी उनको एकड़ के हिसाब से 6 से 9 हजार रूपया जो हो, ऐक्युरेट मुझे याद नहीं है लेकिन जब ब्लौक स्तर पर, अंचल स्तर पर जब सर्वे हुआ तो ऐसे बहुतेरे गांव के लोग हैं, जिनके घर में पानी घुसा हुआ था, उनको 6 हजार के दर जो मिलना था, एक पैसा उनको नहीं मिला और आजतक फसल क्षति के मुआवजे का फाईनल पैसा किसी को नहीं मिल सका ।

सभापति महोदय, पूरे बिहार में मक्का की खेती होती है, हमारे चम्पारण में भी होती है, इस साल 90 परसेंट मक्का में पूरे बिहार में दाना नहीं पकड़ा है । आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सर्वे कराकर मक्का की खेती करनेवाले लोगों को मुआवजा देने का काम करें ।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र बेतिया के मंझौलिया में बीसों सरकारी नल, हर पांच सालों के बाद इलेक्शन होता है मंत्री और महामंत्री का, लेकिन सरकारी पदाधिकारी लोग गरीब मछुआरों के प्रति इतने असंवेदनशील होते हैं, वे लोग मामले को एक दूसरे के लफड़ा में फंसाकर हाईकोर्ट में पहुंचा देते हैं, रजिस्ट्रार के यहां पहुंचा देते हैं और मछली जो बाजार में बिकना चाहिए, वह पदाधिकारियों के घरों में चला जाता है । लेकिन उन मछुआरों को उसका कोई लाभ नहीं मिलता है । तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि उनलोगों की समस्या बैठ करके सरकारी स्तर पर, कानूनी स्तर पर हो, उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम किया जाय ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैविक खाद के लिये सब्सिडी बैंक के माध्यम से दिया गया, मुर्गीपालन के लिये दिया, गौपालन के लिये दिया, बटेरपालन के लिये दिया, सब पर दिया लेकिन आदमी पहचान करके दिया । जो आदमी जिस पंचायत का नहीं है, वह 5 कट्ठा जमीन खरीद लिया है, वह सरकार में प्रभावशाली है, मंत्री का प्रिय है, उसको जैविक खाद का भी लाभ मिला, मुर्गीपालन का भी लाभ मिला, गौपालन लाभ मिला, बटेर का भी लाभ मिला, अब ये टोटल बंद हो करके कौशल विकास हो गया और कौशल विकास का बिल्डिंग भी बन गया, अब इसका भी सब्सिडी उनको मिलेगा क्योंकि ये लोग सरकार के चहेते हैं । तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वैसे लोगों को चिन्हित किया जाय, जिन्होंने सब चीजों पर सब्सिडी का लाभ

लिया और कोई अस्तित्व में नहीं है । ऐसे हजारों लोग जैविक खाद पर जो सब्सिडी लिये हैं, अगर सर्वे किया जाय तो उसमें 60 परसेंट ऐसे लोग पकड़े जायेंगे, जिनके पास अभी जैविक खाद का काम नहीं चल रहा है । या तो वे कहीं नौकरी कर रहे हैं या कहीं बिजनेस कर रहे हैं या भारत के अंदर कहीं कोई रोजगार करके वहां बस गये हैं ।

सभापति महोदय, उसी तरह से कृषि यंत्र की बात है । हर जिला में मेला लगता है लेकिन गृहस्थ को मालूम नहीं होता है । या तो व्यापारी को मालूम होगा या बिचौलिये को मालूम होगा । जिस खुरपी का दाम दुकान में 100 रूपया है, उसी का दाम उस मेला में 200 रूपया है, 100 रूपया आपको सब्सिडी मिल गया तो उस व्यापारी और उस बिचौलियों से बचने के लिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे बिचौलिये को, ऐसे अधिकारियों को जो इस तरह से करते है, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाय अन्यथा कृषि यंत्र के लिये मेला लगाने का काम खत्म किया जाय ।

सभापति महोदय, जब एन.डी.ए. सरकार भारत में आयी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मनरेगा लूट की योजना है । मैं पांच साल मुखिया रहा हूं और 10 साल निर्विरोध प्रमुख रहा हूं । तीसरी बार विधायक बनने का मौका मिला है । मैंने सब योजनओं पर काम किया है । मनरेगा में भी काम किया है । मनरेगा एक ऐसा लोकप्रिय योजना था यू.पी.ए. सरकार का, जिसने गरीबों का पलायन बिहार से रोक दिया। इससे बढ़िया गरीबों का रोजगार का रास्ता नहीं था । अगर कोई गरीब आदमी पांच सौ का नोट देखा तो वह मनरेगा योजना की वजह से ही देखा । आज सड़कों के किनारे जो हरियाली दिखाई पड़ती है, वह यू.पी.ए. सरकार की देन है । यू.पी.ए. सरकार के समय में निजी जमीन पर वृक्षारोपण का कार्य चालू हुआ । निजी जमीन पर पोखरा खोदने का काम यू.पी.ए. सरकार के समय में चालू हुआ । नहर-पईन उड़ाही का काम यू.पी.ए. सरकार के समय में चालू हुआ । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस योजना को प्रतिबंधित नहीं किया जाय । चूंकि मेरे जिला पश्चिमी चम्पारण में मुखिया को पावर दिया गया है मनरेगा से वर्क करने के लिये । लेकिन जिला पर्षद और पंचायत समिति को सरकार के आदेश के बावजूद वहां के कलक्टर अभी तक आदेश नहीं दिये कि समिति और जिला पर्षद् काम करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि समिति और जिला पर्षद् के सदस्यों को भी मनरेगा का काम करने का अधिकार दिया जाय ।

सभापति महोदय, यू.पी.ए. की सरकार में एक और योजना चलायी जा रही थी जिसका नाम था बी0आर0जी0एफ0 योजना, जिससे पिछड़ों और दलितों के इलाके में सड़क और नाली का काम किया जाता था लेकिन एन.डी.ए. की सरकार ने पिछड़ों के साथ दलितों के साथ जो छल किया है इस योजना को बंद करके मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि फिर से बी.आर.जी.एफ. योजना को चालू किया जाय ।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र का एक कंप्लेन करना चाहता हूं । समाज कल्याण मंत्री नहीं हैं । मेरे क्षेत्र में, मेरे पंचायत में और जिस वार्ड में मेरा घर है, उस वार्ड की बात मैं करता हूं । 11 नंबर वार्ड में मेरा घर है, पिपरा-पकड़ी पंचायत है । समाज कल्याण मंत्री संयोग से नहीं हैं ।

(व्यवधान)

हैं ? महोदय, एक वार्ड में एक आंगनबाड़ी केन्द्र होता है लेकिन उनके किसी अधिकारी ने 11 नंबर वार्ड में 4 आंगनबाड़ी केन्द्र खुलवा दिया । यह बहुत गंभीर बात है । इस पर जरा सरकार का ध्यान दिलवाईयेगा । एक वार्ड में 4 आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खुलता है।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री मदन मोहन तिवारी - महोदय, एक मिनट और दिया जाय । मैं अपने क्षेत्र की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जरा सुन लिया जाय । हमारे क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कैंपस है, जिसको बड़ा रमना का मैदान कहते हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर भी जाकर मिला था । वह खंडहर में तबदील हो गया है । उसके सौंदर्यीकरण के लिये सवा करोड़ रूपये का एस्टीमेट बना था, 80 लाख रूपया उसमें खर्च कर दिया गया लेकिन काम कुछ नहीं हुआ । सरकार के चैतन्य जी के सौजन्य से मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जांच भी कराया गया लेकिन अभी तक कुछ रास्ता साफ नहीं दिख रहा है । महोदय, हमारे यहां चन्द्रावत कोहड़ा और अंधरी चोन्धरी नदी है जो सिल्ट से भर गया है । उसमें इन्क्रोचमेंट भी हो गया, जिससे नदी के पानी का बहाव नाली की तरह हो गया है । मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से मांग करूंगा कि वह नदी कम-से-कम बेतिया मंझवलिया के 25 गांवों को छूता है और कृषि के लिये काम करता है । इसलिए उस नदी का सिल्टेशन और अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी ।

टर्न-14/सत्येन्द्र/7-3-14

श्री सुदामा प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ । मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में और सरकार के कृषि मंत्री द्वारा पेश कृषि बजट के खिलाफ में अपनी बात रखूंगा । महोदय, देश और सूबे की खेती लगातार घाटे में जा रही है । सरकार के कॉरपोरेटपरस्त नीतियों के कारण देश के किसान आत्महत्या करने को विवश हैं । मैं बिहार के किसानों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह रास्ता नहीं अख्तियार किया । मुझे दिक्कत हो रही है बोलने में महोदय, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो बिहार में खेती घाटे में जा रही है उसकी मूल वजह है कि कृषि लागत का सामान महंगा हो रहा है और किसानों को उनके उपज का लाभकारी कीमत नहीं मिल रहा है इस वजह से सूबे की खेती घाटे में जा रही है और भू-धारी किसान जो 40 साल पहले स्वयं अपने हाथों से खेती करते थे वे अभी अपनी जमीन बटाई पर लगा रहे हैं । जिन भू-धारी किसानों के पास विकल्प के दूसरे अवसर हैं, वे खेती नहीं करना चाहते हैं और यही वजह है कि बिहार में 80 प्रतिशत खेती बटाई पर होती है और बिहार में घाटे की खेती का भार बटाईदार किसान अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं लेकिन बटाईदार किसानों को खेती की कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है । महोदय, ये जो बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूँ कि यह कॉरपोरेटपरस्त है, ये बिचौलियापरस्त है और खेती का 90 प्रतिशत लाभ जो है बिचौलिये उठा रहे हैं, दलाल उठा रहे हैं और उन्हीं का ब्लौक, बैंकों पर कब्जा है । मैं कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि

जिन बटाईदार किसानों ने घाटे की खेती का भार अपने कंधे पर उठा रखा है, उन बटाईदार किसानों का रजिष्ट्रेशन करावें और उन्हें पहचान पत्र दें । दूसरी मांग मैं ये करता हूँ कि हर साल बिहार में बटाई का रेट बढ़ रहा है, आगे कितने दिनों तक बटाईदार इस घाटे की खेती का भार संभाल पायेंगे कहना मुश्किल है इसलिए बिहार में बटाई के रेट को सुनिश्चत किया जाय, नियंत्रित किया जाय और अनाज का भाव जो है धान का समर्थन मूल्य, मोदी जी ने भी कहा था कि सरकार बनेगी तो लागत का डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य देंगे । मूल्य निर्धारण आयोग ने कहा कि 1 क्विंटल धान पैदा करने में सरकार को 1600/- रू0 खर्च होता है और जो लोग किराये पर खेती करते हैं, बटाई पर खेती करते हैं उनको 2100/- रू0 खर्च होता है लेकिन धान का समर्थन मूल्य जो तय किया केन्द्र की सरकार ने 1550/- रू0, अभी माननीय विधायक जी का भाषण मैं सुन रहा था कि 2022 तक वह दोगुणी आमदनी करेंगे । यहां तो लागत मूल्य में 500/- रू0 का घाटा है, कहां से लागत मूल्य के दोगुणी आमदनी होगी । इसलिए किसानों को वास्तव में धान का समर्थन मूल्य 3200 रू0 होना चाहिए और गेहूं का समर्थन मूल्य जो है वह होना चाहिए 4000 रू0 प्रति क्विंटल । सभापति महोदय, अपने क्षेत्र की एक मांग उठाना चाहता हूँ, कृषि मंत्री जी यहां बैठे है, ये मांग है कि जो मूंजी है वह रोहतास जिले में पड़ता है, मूंजी से लेकर के यहां हरनाथडीह तक करीब 7 कि0मी0 लम्बी दूरी है, मूंजी तक नहर आती है उसको यहां तक विस्तार किया जाय उससे 30 हजार हेक्टेयर खेत का पटवन होगा, ये मैं मांग करना चाहता हूँ कृषि मंत्री जी से और अंत में एक बात अभी इन्होंने कहा कि सरकार कॉरपोरेटों को खेती में लाना चाहती है इसीलिए जानबुझकर के ये खेती को घाटे में डाला जा रहा है ताकि किसान खेती छोड़कर भागे । अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि लीज पर जो किसान खेती करेंगे,महोदय, यहां बिहार में लीज पर खेती नहीं होती है, बटाई पर होती है, लीज पर खेती करेंगे अडाणी, अम्बानी, रिलायंस ग्रुप करेगा और कृषि का सब्सिडी उन्हीं के खाते में जायेगा जैसे कि बीज कम्पनियों को जाता है इसलिए मैं इसकी तीखी निन्दा करता हूँ और इसको बंद करने की मांग करता हूँ । धन्यवाद ।

श्री अरूण कुमारः सभापति महोदय, मैं बिहार सरकार के कृषि बजट पर बोलने के उठा हूँ । महोदय, मैं साफ तौर से बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा हर जगह नकली खाद, बीज मुहैय्या कराया जाता है और यह बजट भी नकली ही है । हमारे साथी बता रहे थे बीज के बारे में, खेती में खाद पानी के अलावा बीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है । यहां माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, बिहार में खाद बीज निगम केवल कागज पर बना हुआ है, कहीं भी बीज उत्पादन नहीं होता है । यहां 80 हजार हेक्टेयर में कृषि फार्म है जो बंजर पड़ा हुआ है, रेगिस्तान जैसा बना हुआ है, एक भी बीज उस कृषि फार्म में उगाया नहीं जाता है, उसकी देखभाल के लिए पदाधिकारी नियुक्त है, तनख्वाह लेते हैं और सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम किसान के लिए अमुक काम कर रहे हैं इतना अनुदान दिया तो हम कृषि मंत्री से अनुरोध करते हैं, कृषि मंत्री जी आप एक विधायक जी से सुन रहे थे पपीता की खेती, यहां लीची की खेती, आप चलें कहीं और वह लिस्ट ले लें, वह पपीता, वह लीची की खेती कौन पंचायत में, कौन गांव में, कौन जिला में कहां है तो नकली जो आप बजट पेश किये हैं मेरा अनुरोध होगा किसान हित में, गांव हित में, गरीब हित में कि उसमें परिवर्त्तन लावें । माननीय कृषि मंत्री जी, मैं

एक बात और कहना चाहता हूँ आज बिहार की जो हालात है, केन्द्र की जो हालात है, अभी 22 हजार किसान केन्द्र सरकार की नीति के चलते और उनके व्यवहार से, उन किसानों के ऊपर जो अभी 50 लाख किसानों के ऊपर जो कर्ज है, आज वह अदा नहीं कर पाते हैं तो उसके विकल्प में उसके पास इच्छाशक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, पूंजी नहीं है तो वह किसान सल्फास की गोली खाकर के, फांसी लगाकर, नदी में डूब कर के, रेल में कटकर के 22 हजार किसान इंडिया में मर गये हैं और हमारे साथी पूरा प्रशंसा कर रहे हैं राधा मोहन सिंह जी का और नरेन्द्र मोदी जी का और प्रशंसा कर रहे हैं हमारे माननीय प्रेम बाबू का भी, हम तो बताना चाहते हैं प्रेम बाबू से कि प्रेम बाबू जो आज हालात किसान की है, यदि आप किसान परिवार से होंगे तो निश्चित रूपेण विपक्ष के माननीय सदस्यों की बात पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए । महोदय, आज जो स्थिति किसान की बनी हुई है, भगवान ऐसा किसी को दुर्दिन नहीं दे, आज खेत में पानी नहीं है, स्टेट ट्यूबवेल सब खराब पड़ा हुआ है, नहर में पानी नहीं है और हमारे यहां कोशी का इलाका जो है उसमें प्रत्येक साल पानी आता है झअुआ खेत में उगता है, बालू का ढेर जमा है, खेत का समतलीकरण नहीं हो पाता है और किसान के हित में आप जो रोड मैप, कृषि मैप तैयार किये हैं, वह कौन कृषि मैप आपका है, यह आपके चीफ सेक्रेटरी के पास रहेगा या किसान के खेत में जायेगा ? आज किसान बेहाल है और आप बोलते हैं, खेती के बारे में आप बोल रहे हैं कि इतना हेक्टेयर में, वह बिल्कुल झूठा है, जो नदी नाला है जिसमें बस्ती बसा हुआ है उसको भी जोड़कर आप रिपोर्ट देते हैं कि इतना खरीफ फसल, इतना रब्बी फसल तैयार है, यह सब बिल्कुल झूठा रिपोर्ट है इसलिए हम निवेदन करेंगे कि किसान हित में निश्चितरूपेण काम हो । महोदय, यही देश था जब पूरी दुनिया में हमारी पूछ थी, दुनिया में हमारा नाम था और यहां इंडिया में भी दूध की नदियां बहती थी और यहां कुटीर उद्योग, हस्तकला उद्योग परकाष्ठा पर था, दुनिया के लोगों में हमारा गुणगान था । आज यहीं देश है जहां के गरीब किसान मजदूर दलित परिवार के लोग हर चीज से अलग है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार नकली बजट बनाकर के लोग को ठग रही है । मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय कि निश्चितरूपेण एक कानून बने, एक नियम बनाया जाय कि बजट का जो आंकड़ा है वह 60 प्रतिशत, 65 प्रतिशत किसान के हित में, खेत के हित में ,खलिहान के हित में गरीब और दलित के हित में हो और इससे ही देश का, इस राज्य का कल्याण होगा । (क्रमशः)

टर्न-15/मधुप/07.03.2018

...क्रमशः ...

श्री अरूण कुमार : किसान के उपर जो ऋण है, 50 लाख किसान के उपर ऋण है, उसको माफ किया जाय । विजय माल्या पैसा लेकर भाग गया ।

(व्यवधान)

यदि वह पैसा आज यहाँ होता तो किसान का ऋण माफ होता, किसान का कर्ज माफ होता। किसान के उपर जो भार बना हुआ है, वह माफ होता लेकिन दुर्भाग्य है कि पैसा लेकर

विदेश भाग गया । माननीय सदस्यों से हम निवेदन करेंगे, कृषि मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा. ..

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो इस सदन के सदस्य नहीं है, आरोप लगाये गये हैं, इसको कार्यवाही से निकाला जाय ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : प्रधानमंत्री जी के बारे में कहे गये आपत्तिजनक अंश को कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अरूण कुमार : सभापति महोदय, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ । जय हिन्द । जय महागठबंधन।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री मेवालाल चौधरी ।

(व्यवधान)

कृपया शांत रहें । विजय प्रकाश जी, शांत रहें । माननीय सदस्य श्री मेवालाल चौधरी ।

श्री मेवालाल चौधरी : सभापति महोदय, कृषि मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है, हम उसके पक्ष में बोल रहे हैं । महोदय, आपकी इजाजत से कुछ बातें जो सदन में हो रही हैं, थोड़ा करेक्शन करना चाह रहे हैं । हमारे कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं मक्का का बीज प्रमाणित होता है । हम माननीय सदस्य से निवेदन करेंगे कि मक्का का बीज कभी प्रमाणित नहीं होता है, जो भी मक्का हमारे यहाँ उगाई जाती है, वह हाइब्रीड मक्का होता है और हाइब्रीड मक्का का मतलब यह होता है कि दो उन्नत किस्म को आपस में क्रॉस करके जो उसका प्रोडक्ट होता है, ऑफ-स्प्रिंग होता है, उसी बीज को हमलोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं । प्रमाणित बीज होता है गेहूँ का, चावल के प्रमाणित बीज होते हैं । (व्यवधान) माननीय सदस्य हम आपकी उस बात को समझ रहे हैं, उसका जवाब हम दे सकते हैं लेकिन हमने माननीय कृषि मंत्री जी से भी पूरी डिटेल में बात की है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ है ।

सभापति महोदय, अभी हाल में महामहिम राज्यपाल जो एग्रेरियन बिल, चम्पारण सत्याग्रह के उपर जो भाषण दे रहे थे, बड़े स्पष्ट शब्द में उन्होंने कहा कि अगर कोई द्वितीय हरित क्रांति किसी भी राज्य से शुरू होगी तो वह बिहार राज्य है । कोई भी राज्य देश में ऐसा नहीं है । इसके पीछे बहुत कारण है । महोदय, हमारा बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर होरीजेंटल एक्सपैंशन, वर्टिकल एक्सपैंशन का स्कोप है, किसी भी अन्य राज्य में पूरे देश में ऐसा होरीजेंटल एक्सपैंशन का कोई स्कोप नहीं है । महोदय, आज से कुछ साल पहले हमारा जो भी एरिया का ग्रोथ हो रहा था, हमलोग निगेटिव में जा रहे थे लेकिन अगर पिछले दो साल का डाटा देखेंगे, हमलोग सिगनिफिकेंटली प्रोग्रेस किये हुये हैं और एरिया के निगेटिव ग्रोथ से निकल कर हमलोग पोजिटीव ग्रोथ में जा रहे हैं जिसके कारण आज जो चावल के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आज जो गेहूँ के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आज जो सब्जी के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, महोदय, हम फिगर देना चाहेंगे या हम समय बचाने के लिये सिर्फ परसेंटेज में बात करना चाहेंगे । तकरीबन 10 परसेंट से लेकर 21 परसेंट तक की बढ़ोत्तरी हुई है । महोदय, हमें समझ में नहीं आता है कि आज से 10 साल पहले हमलोग

फूड डेफिसिट स्टेट थे लेकिन आज हमलोग फूड सरप्लस नहीं हैं तो कम से कम हमलोग चावल और अनाज इतना पैदा करते हैं कि हम अपने आप में कंज्यूम कर लेते हैं । आज सब्जी प्रोडक्शन में हमलोगों ने एक सिगनिफिकेंट रेकर्ड पैदा किया है जो पूरे भारत के लिये एक मिसाल है । आज हमलोग पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पैदा कर रहे हैं । इसके पहले हमलोग चौथे स्थान पर थे, हमलोग तीसरे स्थान पर थे, यू0पी0 और वेस्ट बंगाल के बाद हमलोगों का नम्बर आता था लेकिन महोदय, आज बड़ी खुशी होती है कि हमारा राज्य कृषि के मामले में जो प्रोग्रेस कर रहा है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि इतने अच्छे सुसज्जित स्कीम्स, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय कृषि मंत्री द्वारा जो इंटेंसिव टूर किये जा रहे हैं पूरे बिहार में, उसकी बदौलत हमलोग बड़ा सिगनिफिकेंट ग्रोथ किये हैं ।

महोदय, कृषि रोड मैप जो बड़ा ही बिहार के लिये उपयोगी रोड मैप है जिसमें हम सिर्फ तीन बात का जिक्र करना चाहेंगे, बहुत सारी बातें माननीय सदस्य महोदय ने कहा है । इसमें जो सबसे अच्छी बात है, आजकल मार्केट में हमलोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, जिसके लिये हमलोग कलस्टर एप्रोच को प्रोमोट करना चाहते हैं, हमलोग संगठित फार्मिंग को प्रोमोट करना चाहते हैं, हमलोग सामूहिक फार्मिंग को प्रोमोट करना चाह रहे हैं, हमलोग ग्रुप एप्रोच करना चाह रहे हैं । महोदय, आज के जमाने में इंडिविजुअल फार्मिंग होती है, एक आदमी अपना किसानी करता है, बिचौलिया आते हैं, मिडिलमैन आते हैं या साहूकार आते हैं, मन-मर्जी से रेट लगाकर खरीद कर चले जाते हैं । जब हम कलस्टर फार्मिंग शुरू करेंगे, जो कंसेप्ट हमारे रोड मैप में हैं, इससे हमारी बारगेनिंग पावर बढ़ेगी । हमको कोई ठग नहीं सकता है चूंकि यह ग्रुप का होगा और उस ग्रुप में सिर्फ एक ही लीडर होगा, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हमारी बारगेनिंग पावर बढ़ जायेगी और जो भी साहूकार हैं उनके साथ जितनी हमारी मर्जी होगी, हम बारगेनिंग करेंगे, न कि हम उनकी बात सुनेंगे । इंडिविजुअल फार्मिंग के समय हम उनकी बात सुनते हैं और औने-पौने दाम में अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं ।

महोदय, बहुत सारी बातें हुई ऑरगेनिक फार्मिंग के बारे में, हम एक ही चीज कहना चाह रहे हैं कि आज का जमाना है कि हमलोग दवाई तो खा रहे हैं, बहुत सारे आर्टिफिसियल कैप्सूल्स खा रहे हैं कैलसियम के लिये, आयरन के लिये और जब भी आजकल अच्छे डॉक्टर से बात करेंगे, सबलोग कहते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू को बढ़ानी है। यह सब्जी ऐसे हैं, फल ही ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू होती है जिसमें हर तरह के न्यूट्रेंट्स होते हैं । आज जो ऑरगेनिक फार्मिंग का कोरिडोर डेवलप किया जा रहा है, एक तो हमलोग उसमें ऑरगेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ऑरगेनिक पेस्टीसाइड यूज करेंगे, जिसके कारण हमलोग आज जो सब्जी ला रहे हैं, ऑनेस्टली हम भी कह रहे हैं, हमलोग पहले बॉयल करके ही सब्जी को बनाते हैं, डायरेक्ट सब्जी को बनाने का मतलब हमलोग पेस्टीसाइड्स कंज्यूम कर रहे हैं । आज तकरीबन 23 परसेंट पेस्टीसाइड्स बैंगन, भिंडी या जो भी ऑफ-सीजन क्रॉप निकल रहा है, सबमें पेस्टीसाइड्स का बहुत यूज हो रहा है । पेस्टीसाइड मतलब इंसेक्टीसाइड या फंजीसाइड, जो भी हो, बहुत सारे पेस्टीसाइड्स का यूज हो रहा है । जब हम ऑरगेनिक फार्मिंग करेंगे, इससे क्या होगा कि एक तो उस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा, उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी, उसका न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू मेन्टेन रहेगा और मार्केट में अच्छे

दाम पर बिकेंगे । जो नारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री का है कि हम किसानों को आय बढ़ाने में मदद करेंगे, इससे हमलोग बहुत सारा आय बढ़ा देंगे ।

महोदय, हम अगर थोड़ा-बहुत एनीमल हसबैंड्री की बात करें, हमलोग कहते हैं गोटरी फार्मिंग को - The poor man's farming सिर्फ गरीब तबके के लोग इस तरह के फार्मिंग में, जो बकरी पालते हैं, व्यस्त रहते हैं ।

...क्रमशः ....

टर्न-16/आजाद/07.03.2018

..... क्रमशः ....

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, बकरीपालन एक ए0टी0एम0 कार्ड है । अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो पूरे साल में वह कम से कम 6 बच्चे देंगे और उसकी जो भैल्यू होती है हर महीने परपोसनेटली बढ़ता है और वह आय का स्रोत हो जाता है ।

महोदय, फिश फार्मिंग में मैंने कहा था कि बिहार में जितने भी डिफिसीट स्टेट थे, आज हमलोग बिहार सेल्फ सफिसियेन्ट स्टेट हैं फीश प्रोडक्शन में । हमारी फीश का रिक्वायरमेंट 5.6 लाख मे0टन था । आज हमलोग फीश ऑलमोस्ट 5.5 लाख मे0टन पैदा कर रहे हैं । जो इम्पोर्ट हैदराबाद से पटना होता था, जो इम्पोर्ट हैदराबाद से बिहार होती थी । आज अगर उसके परपोसनेट देखेंगे पिछले दस साल से हमने बहुत ही सिग्नीफिकेन्टली फायदा किया है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : कृपया आप समाप्त करें ।

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम हनी प्रोडक्शन के बारे में बोलना चाहेंगे, दो मिनट का समय दे दिया जाय सर । महोदय, हनी प्रोडक्शन आपके राज्य का सबसे ज्यादा पैदावार करता है, 45हजार मे0टन पैदा कर रहा है । महोदय, आपके हनी को लेकर के एडल्टेशन ऑफ हनी नेपाल से लोग लाकर के, एडल्ट करके बिहार में हनी बनाते हैं । मुझे जरूरत है महोदय, इसको कलस्टर एप्रोच में पार्क करने का और इस पार्क को बना लेंगे । महोदय, थोड़ी सी दो-चार सजेशन हैं जो सरकार को अपनी तरफ से देना चाहेंगे । महोदय, हमलोग जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन, टेम्परेचर, रैन फॉल को देखते हुए सरकार को विश्वविद्यालय के साथ एक नीति तय करनी चाहिए कि हमारे पास क्या प्रोटोकॉल है । महोदय, हम एक निवेदन करना चाहते हैं माननीय कृषि मंत्री से कि आज टेक्नोलॉजी बेस्ड, नॉलेज बेस्ड साईंस हो गया है, हम नॉलेज बैंक की स्थापना करना चाहते हैं पंचायत स्तर पर । महोदय, हमारे जितने भी फार्म स्कूल हैं, उस फार्म स्कूल को के0वी0के0 को हैंडओभर कर दिया जाय और के0वी0के0 के साईंटिस्ट को रिसपौंसबीलीटी दिया जाय कि आप उस फार्म को चलाये ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : कृपया आप समाप्त करें ।

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, एक मिनट सर, संग्रामपुर में सरकार का फार्म है, तारापुर, संग्रामपुर में 20-20 एकड़ का फार्म है, जिसका लैंड कोई यूज नहीं होता है । महोदय, स्वायल फर्टिलिटी का बहुत बड़ा जमाना है । हम माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करेंगे कि संग्रामपुर में एक

स्वायल एनालाईसिस लेबोरेटरी की स्थापना करें और कॉमर्शियल नर्सरी की स्थापना करें ताकि लोगों को भी वहां पर इमप्लायमेंट मिलेगा और किसानों को भी मजबूती होगी ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद जी ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री मो0 इलियास हुसैन : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को एग्रेरियन पर बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं, ऐसी चीजों को सदन में सुनना चाहिए, इसलिए मेरा सुझाव होगा कि इनको बोलने का मौका दिया जाय ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य, आप बोलिए ।

श्री मेवालाल चौधरी : थैंक यू महोदय, बहुत,बहुत धन्यवाद । महोदय, हम दो–चार सजेशन सिर्फ सरकार को देना चाह रहे हैं । महोदय, मैंने क्लाईमेट चेंज की बात की, आज जरूरत है महोदय एक अच्छे प्रोटोकॉल डेवलप करने का । क्रौप्स बेस्ड प्रोटोकॉल की जरूरत है, अगर धान लगानी है तो महोदय इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, रैन फॉल पैटर्न इतना शिफ्ट कर रहा है । अगर हमको अपना प्रोटोकॉल नहीं है और क्लाईमेट वेरीयेशन में हम कोई क्रौप्स ग्रो नहीं कर पायेंगे तो हमारे किसान सफर करेंगे । सबसे बड़ी बात है महोदय किसानों को इसके प्रति जागृत करना । अगर किसान इससे जागृत नहीं होते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी अगर किसानों के खेत में ट्रांसफर नहीं होते हैं तो महोदय वह नहीं हो पायेगा। हमने नॉलेज बैंक की बात की है, हमने कहा कि एक केन्द्रीयकृत बैंक होनी चाहिए ज्ञान का । महोदय, आज टेक्नोलॉजी बेस्ड, आज बिना नॉलेज बेस्ड क्रौपिंग नहीं हो सकता है । महोदय, मैंने कहा कि हमारे जितने भी एग्रीकल्चर स्कूल चल रहे हैं, उसमें दिन में खानापूर्ति हो सकता है लेकिन महोदय, ऐसे स्कूल जो चूँकि हमारे किसान मॉरनिंग से इवनिंग तक खेती में बीजी रहते हैं, वे एटेंड नहीं कर पाते हैं सिरियसली महोदय । हम महोदय, ऐसे स्कूल अगर हम शाम में चलाये और ऑडिया–विजुअल के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से उनको दिखाये कि धान का जो नॉलेज बेस्ड फार्मिंग कैसे होता है, जापान में क्या हो रहा है, चाईना में क्या हो रहा है और पंचायत बेसिस पर चलायें तो शायद बहुत बड़ा फायदा होगा ।

महोदय, हम सीड प्रोडक्शन की बात करना चाह रहे हैं । हमलोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहे हैं । हमारा निवेदन होगा कृषि मंत्री जी से, सर आर्गेनिक खेती के लिए ऑर्गेनिक शीड चाहिए । हमलोग उसके लिए कितना तैयार हैं, मेरा एक सुझाव होगा कि सरकार के जितने भी फार्म हैं, वे सब फार्म बड़ा उपयोगी फार्म है, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं शीड प्रोडक्शन के लिए । हम चाहते हैं कि जो इनके डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट के0वी0के0 के इनचार्ज हैं, उनकी ज्वायंट रिसपौंसबीलीटी दी जाय और उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली फिक्स कर दिया जाय कि सीड प्रोडक्शन के कारण अगर कोई फेल होता है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी । उसके एकाऊंटबीलीटी भी फिक्स कर दिया जाय ।

महोदय, दूसरी समस्या जो आने वाली है, हम अपनी बात कह रहे हैं । हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि बिहार पल्स में एक लीडिंग स्टेट है, हमारी प्रोडक्टवीटी नेशनल प्रोडक्टवीटी से ज्यादे है । लेकिन जिस तरह से आर्गेनिक कॉरीडोर डेवलप किये, जरूरत है कि एक पल्स कॉरीडोर डेवलप करें । चूँकि अभी भी हमलोग तकरीबन कुछ शोर्टेज है पल्स

में, हमारे प्रोडक्शन उतनी नहीं हो रही है, जितना हमारी कंजम्पसन हो रही है । महोदय, फोरचुनेटली और अनफोरचुनेटली जिसको हम लेंटिल कहते हैं, वह शिफ्ट हो रहा है चना से। आजकल चना कोई लगाना नहीं चाह रहा है, इसमें बीमारियां आती है, इसलिए इसपर ध्यान देने की जरूरत है ।

महोदय, मैं एक चीज और माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि कुछ स्पेशीलिटी ऑफ क्रौप को डेवलप करें । महोदय, ओनियन, प्याज कितना बड़ा महत्वपूर्ण क्रौप है, हम प्याज खासकर के अक्टूबर, नवम्बर में 40रू0-50 रू0 खरीदते हैं । महोदय, हमारे पास इतने अच्छे प्याज के रेंज हैं, इतने अच्छे लोकेलिटी है, पूरे नालन्दा से लेकर के पूरा एक रेंज है लखीसराय तक, महोदय, मेरे कहने का मतलब कि अगर हम इसके लिए स्टॉरेज फैसिलीटीज प्याज के लिए इतने अच्छे ढंग से डेवलप करें ताकि जो प्याज की रिक्वायरमेंट है, हम उसको फुलफील बिहार से कर सकें । हम महाराष्ट्र की प्याज पर डिपेंडेंट नहीं हों, हम राजस्थान के प्याज पर डिपेंडेंट नहीं हों, इसीलिए हमलोग इसको स्पेशल क्रौप में इनक्लूड करें।

महोदय, मखाना जो आपके स्टेट का स्ट्रेन्थ हैं, मजबूती है, जिसको हमलोग वर्ल्ड के मैप में डाले हैं । मखाना प्रोसेसिंग, हमलोग अभी भी माइक्रो प्रोसेसिंग करते हैं, बाहर के लोग मखाना उठाकर ले जाते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करके जो मखाना हमारे यहां दाम में बेचता है, उससे दस गुना दाम में बाहर जाकर बेचता है । लेकिन महोदय, अगर हमलोग इसमें प्रोसेसिंग पर ध्यान दें तो शायद हमलोग इसमें बहुत पैसा कमायेंगे और हमारे पास और पैसा आयेंगे । मैंने हनी की बात की, मैं बीच में भूल गया, हम कृषि मंत्री जी से निवेदन करेंगे चूँकि हमलोग हनी का लीडिंग स्टेट है, हमारा हनी ही प्योर हनी है, हमलोग इसको ब्राडिंग कर दें, कोई नाम दे दें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हरेक व्यंजन में एक व्यंजन जरूर बिहार का हो । महोदय, अगर हम हनी का ब्रांडिंग कर दें तो शायद बिहार का नाम कमायेंगे ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : कृपया, अब आप समाप्त करें ।

श्री मेवालाल चौधरी : एक मिनट महोदय, एक सवाल था महोदय, हम दोबारा एक स्वायल फर्टिलिटी के बारे में बोलना चाहेंगे । दो मिनट सर । स्वायल फर्टिलिटी का मैप बना हुआ है, वह सरकार के पास है । हम माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि स्वायल फर्टिलिटी मैप पंचायत स्तर पर डिसप्ले कर दें, उसमें खाता, खेसरा नम्बर से स्वायल को एनालाईसिस किया गया है । उसमें लिखा हुआ है कि फंलाने खेसरा में कितना न्यूट्रेंट डिफिसियेन्सी है, नाइट्रोजन डिफिसियेन्सी है, फॉस्फोरस डिफिसियेन्सी है, उससे महोदय किसान को जो एक्सैस यूज ऑफ फर्टिलाईजर हो रहा है, उसके कारण हम ज्यादा लागत कर रहे हैं, उस लागत को कम कर सकते हैं । महोदय, एक मिनट और हमारे तारापुर में भी तकरीबन 14 एकड़ का सरकार का फार्म है, वह भी बड़ा उपयोगी फार्म है । उसमें भी अगर उसी तरह का हाई डेनसीटी और उसमें अगर कॉमर्शियल नर्सरीज के रूप में उसको व्यापार की तरह बना दें तो किसानों को उससे फायदा मिलेगा ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : कृपया आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री मुद्रिका प्रसाद राय ।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : सभापति महोदय, मैं कृषि विभाग के बजट के विपक्ष में तथा कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । जैसा कि सदन में सभी सदस्यों ने कृषि विभाग के बजट पर काफी कुछ चर्चाये की और कृषि से जुड़े हुए कई मुद्दों को उठाया लेकिन कृषकों के समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे । सबसे बड़ी जो समस्या है, वह है पशुओं के द्वारा जैसे पूरे राज्य में नीलगाय, सूअर का आतंक जो है, वह किसानों को बहुत क्षति पहुँचा रहा है । फसल बर्बाद हो रही है और किसान मारे जा रहे हैं । इसपर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं ।

..... क्रमशः ......

टर्न-17/अंजनी/दि0 07.03.2018

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : ...क्रमशः.... गन्ना किसान जो हमारे क्षेत्रों में खेती करते हैं, हमारा दियारा क्षेत्र है, काफी बड़ा दियारा क्षेत्र है और दियारा क्षेत्र में किसान गन्ना, धान या गेहूँ की खेती करते हैं तो उन खेतों में नील गाय, सूअर आदि छिपकर रहते हैं और किसान जब फसल काटने जाता है तो उनकी हत्या कर देते हैं तो ऐसी स्थिति हो गयी है । अभी चार-पांच दिन पहले की घटना है कि तरैया के दियारा क्षेत्र में किसान गया गन्ना काटने के लिए तो सूअर ने उनपर आक्रमण किया और उसकी मौत हो गयी तो यह स्थिति है पूरे बिहार में । चाहे गन्ना फसल हो, धान फसल हो या गेहूँ की फसल हो पशुओं से बचाव के लिए सरकार को इसपर विचार करना चाहिए । ऐसे मुख्यमंत्री जी ने एक बार सदन में मामला उठाया था, सूअर और नील गाय को मारने की बात आयी थी कि यह वन्य जीव संरक्षण से मुक्त है, इनकी हत्या यदि कोई करता है तो कोई दोष नहीं लगेगा या उनपर कोई कार्रवाई नहीं होगी । लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर किसान इनकी हत्या करे तो कैसे ? उसके लिए कौन सा साधन किसानों के पास उपलब्ध है, यदि वे इसका शिकार करते हैं तो अगर वे निजी बन्दूक या अवैध तरीके के हथियार हैं, अगर उससे करते हैं तो कानूनी तौर पर वे फंस जायेंगे । यदि इनका लाईसेंसी हथियार है तो उनका लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा कि शिकार करने के लिए उनको लाईसेंस नहीं मिला है । आखिर वे अपना संरक्षण करें तो कैसे ? इसपर सरकार को विचार करना चाहिए । जहां तक राज्य में गन्ना उद्योग की बात है, गन्ना किसान की बात है तो हमारे सारण जिला में मढ़ौरा चीनी मिल जो वर्ष 1997 में बंद हुआ, उसकी बड़ी सम्पत्ति को वहां के स्थानीय दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है । जो सुगर मिल का जमीन था, अभी हाल के वहां के अखबारों में छपा है कि 260 एकड़ जमीन वहां के दबंग लोगों ने ट्रैक्टर से जोतकर कब्जा कर लिया है और कब्जा करने का जो आधार बनाया गया है, वह जाली कागजातों के आधार पर । वे लोग बता रहे हैं कि चीनी मिल को हमलोगों ने लीज पर दिया था और चीनी मिल चूंकि बंद हो चुका है तो अब यह लीज मुक्त हो चुका है, हम अपना कब्जा इसपर कर लेंगे । लेकिन सरकार का जो खाता-खतियान है, उसमें दर्ज है, वह चीनी मिल के नाम पर दर्ज है और किसी को कोई अधिकार नहीं है उसपर कब्जा करने के लिए । वर्ष 2006-07 तक कानपुर सुगर मिल जो है, वह लगान देते रहा है तो ऐसी स्थिति में उसपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए । वहां के जो सी0ओ0 और थाना प्रभारी हैं, वे इसके लिए जिम्मेवार हैं चूंकि सी0ओ0 ने ही लोगों को उकसाया था कि आप लोग अब कब्जा कर सकते

हैं । लेकिन जब यह मामला वहां के स्थानीय लोगों ने उठाया कि यह जो जमीन है, अब सरकार की है, यह कैसे कोई लीज पर ले सकता है । लीज कभी किसी ने किया नहीं है । चूंकि 200 वर्षों से अंग्रेजी शासन था और उस समय का मालिकाना हक सुगर मिल के पास था तो आज ये लीज इन लोगों ने कैसे दे दिया वहां के अंचलाधिकारी ने तो यह परिस्थिति है। वहां पर एक और जमीन है, जो कृषि अनुसंधान केन्द्र का है जो साठ एकड़ में फैला हुआ है। कृषि अनुसंधान केन्द्र वर्ष 1996-97 तक चला है और अब वह बंद हो जाने के बाद वहां के एक नेता द्वारा उसपर कब्जा कर लिया गया है और ए0डी0एम0, सारण द्वारा उसको दााखिल-खारिज करने का आदेश उनके नाम पर कर दिया गया है, जो अवैध है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय :तो हमने सी0ओ0 से यह बात बता दिया है कि इसको दाखिल-खारिज न करे लेकिन जिस पदाधिकारी ने दाखिल खारिज करने के लिए आदेश किये हैं उनपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, यह हम सदन से मांग करते हैं । साथ-ही महोदय, गन्ना मंत्री जी तरैया गये थे और इन्होंने अखबार में बयान दिया कि सरकार मरौढ़ा चीनी मिल को चालू करने पर विचार कर रही है । यदि सरकार की ऐसी भावना है, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है तो हम सदन के माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे लेकिन यदि ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो हम मांग करते हैं कि पुन: एक बार इसके लिए प्रयास होना चाहिए । इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ । धन्यवाद ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्यगण, सरकार का उत्तर, माननीय मंत्री, कृषि विभाग।

सरकार का उत्तर

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कृषि विभाग द्वारा सदन में पेश किये गये बजट पर माननीय विधायकगण श्री भोला यादव जी, डा0 रामानुज प्रसाद जी, श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, श्री मनोज कुमार जी, श्री विनय वर्मा जी, श्री विजय प्रकाश जी, श्री निरंजन कुमार मेहता जी, श्रीमती अरूणा देवी जी, श्री मदन मोहन तिवारी जी, श्री सुदामा प्रसाद जी, श्री अरूण कुमार जी, श्री मेवा लाल चौधरी जी, श्री मुद्रिका प्रसाद राय जी ने बहुत कीमती सुझाव देने का काम किया है । माननीय सदस्यों का जो सुझाव आया है, निश्चित तौर पर उन बातों पर सरकार गौर करेगी । कई बातों की चर्चा की गयी है । सभापति महोदय, हम प्रारम्भ करना चाहते हैं मशहूर किसान कवि घाघ ने कहा है " उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान" । महोदय, प्राचीन काल से ही कृषि को सबसे उत्तम जीविका का साधन माना गया है । खेती सबसे सम्माननीय कार्य माना गया है । परंतु वर्त्तमान में जलवायु परिवर्त्तन के परिप्रेक्ष्य तथा जनसंख्या के बढ़ते दबाव से कृषि योग्य भूमि में कमी आयी है । इन परिस्थितियों के बीच वर्त्तमान की केन्द्र एवं राज्य की सरकार टिकाऊ खेती के साथ-साथ किसानों के प्रति जो प्रधानमंत्री जी का पहल है और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि किसानों की आमदनी दुगुनी हो, इसे पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ सतत् प्रयत्नशील है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, देश में पूर्ववर्त्ती सरकारों द्वारा कृषि के संधारणीय विकास यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए चरणबद्ध ढंग से काम नहीं किया गया है, जिसके कारण कृषि के समक्ष

कई चुनौतियां उत्पन्न हुई है । महोदय, बिहार संभवत: देश का पहला राज्य है, जहां कृषि के चरणबद्ध विकास के लिए कृषि रोड मैप बनाया गया है और इसके लिए बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ । साथ ही साथ, कृषि के क्षेत्र में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिये माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ । हमारी सरकार कृषि को पुन: सम्माननीय एवं लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है ।

महोदय, कृषि के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि हमारा जीवन ही कृषि पर आधारित है । महोदय, कृषि का विकास ही समग्र विकास की कुंजी है । परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल और मानवशक्ति की उत्पादक क्षमता का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाये । बिहार में कृषि के विकास से ही आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा, साथ-ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ।

महोदय, हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति ने बिहार को बहुत ही उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधनों का वरदान दिया है । साथ ही, यहां कृषि जलवायु की विशाल विविधता है जो बागवानी तथा औषधीय पौधों सहित बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती के लिए काफी अनुकूल है । बिहार गंगा की तराई में बसा है । यहां भूगर्भीय जल काफी मात्रा में है । सब्जियों की पैदावार में हम देश के तीसरे स्थान पर हैं । मखाना, लीची पैदा करने में भी हम सबसे आगे हैं । अनानास, आम, केला, अमरूद, गन्ना, जूट आदि पैदा करने में भी हमारी श्रेष्ठता स्थापित है । जरूरत है तो बस इसके लिए बेहतर बाजार की व्यवस्था करने की । महोदय, हमारी सरकार किसानों के लिए दो कृषि रोड मैप बिहार में तैयार की है। महोदय, 2008 से लेकर और दूसरा 2012 में है । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 76 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है और यहां की कृषि जी0डी0पी0 राज्य के जी0डी0पी0 का पांचवां हिस्सा है । राज्य में कुल 13 मिलियन कृषि परिवार के पास 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन है ।

....क्रमश:...

टर्न-18/शंभु/07.03.18

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : क्रमश:........जहां देश में औसतन 42 परसेंट जमीन पर खेती होती है वहीं बिहार में 60 परसेंट जमीन पर खेती होती है । महोदय, आज जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है और हमारा बिहार भी प्राकृतिक आपदाओं से अछूता नहीं है । यहां के 90 परसेंट जिलों को सुखाड़ एवं बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है । इसके बावजूद हमारे अन्नदाता किसान दिन रात मेहनत कर राज्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए नि:स्वार्थ भाव से लगे रहते हैं । यह राष्ट्रभक्ति की पराकाष्ठा है - आसमान पर नजर हमेशा, वे आंधी तूफान सब सहते हैं, खेतों में हरियाली आये, दिन रात लगे हुए रहते हैं, मेहनत करके हमेशा वह पेट सभी का भरते हैं, वह है मसीहा मेहनत का उनको किसान हम कहते हैं ।

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 2008 में कृषि रोड मैप यहां लॉन्च किया गया था और 2012 में यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि चावल का

रिकार्ड उत्पादन हुआ, 2013 में गेहूँ का रिकार्ड उत्पादन हुआ और 2016 में मक्का का रिकार्ड उत्पादन हुआ । मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के किसानों के कठिन परिश्रम और राज्य सरकार के सहयोग से बिहार कृषि के क्षेत्र में कृषि कर्मण पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा पहली बार राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है । महोदय, आपके माध्यम से हम सदन को बताना चाहते हैं 17.03.2018 को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के द्वारा फिर एक बार बिहार के किसानों के लिए बिहार सरकार को राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा जायेगा । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि कृषि रोड मैप के मामले में सरकार का जो लगातार प्रयास है और हमारी जो प्राथमिकता है आर्गेनिक खेती । किसानों की आमदनी दुगुनी कैसे हो । हमने हाल में अभी पहली बार जब कृषि मंत्री बनने के बाद हमें लगा कि किसानों के सामने कई चुनौतियां हैं और हमने विभाग के अधिकारियों को कहा हम सबों को चलना चाहिए किसानों के बीच और आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के सभी पंचायतों में हमने पहली बार किसान चौपाल लगाया है और उस किसान चौपाल में रिकार्ड हमारे पास कोई साथी देखना चाहेंगे इन बातों को देख सकते हैं- बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उस किसान चौपाल में बड़ी संख्या में किसान आए । महोदय, 5 लाख 97 किसानों ने भाग लिया और 4 हजार 190 सुझाव किसानों से प्राप्त हुए हैं । मैं स्वयं गया था- नालन्दा जिले में, रोहतास जिले में किसान चौपाल में मैं स्वयं भाग लिया था और हमारे अधिकारी भी, हमारे ए0पी0सी0, प्रधान सचिव, विभाग के सभी पदाधिकारी । हमने आगे प्लैन किया है कि जो हम 2018-19 का बजट ला रहे हैं, हमने प्रावधान किया है कि हम तीन चौपाल लगायेंगे- एक लगायेंगे खरीफ फसल के पहले, दूसरा हम लगायेंगे रबी में और तीसरा हम लगायेंगे गरमा में । हमने तय किया है कि राज्य की सरकार कृषि विभाग तीन चौपाल लगायेगा और तीन चौपाल के माध्यम से हम राज्य सरकार की योजनाओं से, भारत सरकार की योजनाओं से और हमारा जो कृषि रोड मैप है उससे हम किसानों को जोड़ना चाहते हैं । हमारा प्रयास है कि राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए हमने एक और फैसला लिया है । हमारे पास ई-किसान भवन है सभी प्रखंडों में और जहां जमीन उपलब्ध हुआ है हमने ई-किसान भवन बनाया है । किसान लंबी दूरी तय करके प्रखंडों में आते हैं इसलिए हमने फैसला लिया है कि राज्य के जो अन्नदाता किसान भाई बहन हैं, हमने निर्णय लिया है कि अगले वित्तीय वर्ष में पंचायत स्तर पर किसानों के लिए कार्यालय खोला जायेगा । हम किराये के मकानों में खोलेंगे और राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज में 1 हजार पंचायती राज सरकार भवन बना है । हमारे किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक हमने तय किया है कि उनको प्रखंड में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी । हमारे किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक पंचायतों में बैठेंगे और किसानों का साथ देंगे, यह हमारी योजना है । जो काम ये 15 वर्षों में नहीं कर पाये, बीज निगम बंद हो गया था इनके जमाने में और हम सरकार में जब आये तो बीज निगम को हमने फिर से चालू करने का काम किया । यह हमारे सरकार की उपलब्धि है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज मिट्टी है, किसानों का स्वायल है- हमने तय किया है कि माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं किसानों की जो खेती है, जो मिट्टी है उसके लिए स्वायल हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं । हमने अभी तक बड़े पैमाने पर राज्य के किसानों को जो सिंचित भूमि हमारी है, असिंचित भूमि है ढाई हेक्टर में सिंचित और 10 हेक्टर का हमने असिंचित फिल्ड बनाया है । उसके माध्यम से राज्य के किसानों को हम स्वायल हेल्थ कार्ड

दिया है और हमने तय किया है कि रबी कटने के बाद स्वायल हेल्थ कार्ड लेकर के हम किसानों के साथ बैठेंगे और किसानों को बताना चाहेंगे कि आपके खेतों में किस तत्व की कमी है । 13 तरह के तत्व पाये जाते हैं - जिंक की कमी हो, फास्फोरस की कमी हो जिस तत्व की कमी होगी हम किसानों को इस बात से परिचय करायेंगे, चूंकि किसान जाने अनजाने में खेतों में खाद का ज्यादा प्रयोग कर जाते हैं । उससे किसानों का लागत कमेगा और उत्पादन बढ़ेगा और मिट्टी की सेहत बेहतर रहेगा, यह हमारा प्रयास है । इतना ही नहीं सिंचाई के मामले में जो साथी हमारे कह रहे थे, हम साथियों को बताना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं.........जाइयेगा नहीं लेकिन ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : हॉं, इसीलिए तो आपको सुन रहे हैं आराम से मदद कर रहे हैं । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में कई बार कहा है कि 2-4 या 10 कट्ठा जमीन वाले भी जो शहर में रहते हैं, आजकल वे खेती नहीं कर रहे हैं और खेती कर रहा है वो जो गरीब, मजदूर, किसान, दलित है, वही या तो बटाईदारी करता है या पट्टे पर खेती लेता है । मगर जब कोई प्राकृतिक विपदा आती है, तब जो फसल क्षति का लाभ है वह बटाईदार को नहीं मिलता है । इसलिए बटाईदार जो अपना खून, पसीना एक करके खाद, पानी सब लगाकर निकौनी करके खेती करता है तो कम से कम उसका आईकार्ड बनवाइयेगा, रजिस्ट्रेशन करवाइयेगा और उसको फसल क्षति का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ? इसपर न बोलिए ।

अध्यक्ष : सिद्दिकी साहब, यह मामला तो आपदा प्रबंधन विभाग में आयेगा कृषि विभाग इसमें क्या करेगा?

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि जिन कामों को 15 वर्षों में नहीं कर पाये, हम एक साल में करके दिखाये । इनके सवालों का हम जवाब देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं भागिए मत, रहना पड़ेगा ।

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

हम कहना चाहते हैं यह बात सही है राज्य में हमारे पास दो तरह के किसान हैं- 15 वर्षों में बिहार को गड्ढे में ले जानेवाले लोगों को कोई अधिकार नहीं है और हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने तीसरा कृषि रोड मैप लाने का काम किया है। 9 नवम्बर, 2017 को इसी पटना के बापू सभागार में देश के लोकप्रिय राष्ट्रपति हमारे महामहिम रामनाथ कोविन्द जी आये थे, उनके हाथों हमलोगों ने 9 नवम्बर को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1 लाख 54 हजार 635 का कृषि रोड मैप कैबिनेट से पास करवाया है । हमारी सरकार है और सरकार की पहली प्राथमिकता है गांव, गरीब, किसान- हमारी सरकार जानती है........क्रमशः।

टर्न-19/अशोक/07.03.2018

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : क्रमशः... हमारी सरकार जानती है कि राज्य की बड़ी आबादी है, राज्य की हमारी अर्थ व्यवस्था जो है, राज्य की जो बड़ी आबादी है, वह कृषि पर आधारित है । 12 विभागों के समन्वय से कृषि विभाग ने 21 हजार 612 करोड़ बजट हमने बनाया महोदय । अभी हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि बजट कम कर दिया गया । मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि बजट महोदय कम नहीं हुआ है, हम डीजल में रखे हुये थे महोदय 175 करोड़, अब गांव-गांव में बिजली चली गई महोदय, डीजल का खर्च हमारा कम हो रहा है तो हमने

बजट में 100 करोड़ की कटौती कर दी । महोदय, हमारा जो राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय है उसका खर्च बजट में जो रहता था उसमें कमी आई महोदय । बजट कमा नहीं बल्कि आने वाले समय में हम बतलाना चाहते हैं कि प्रयास हम कर रहे हैं । सिंचाई की चिंता लोग कर रहे थे, राज्य के 17 जिलों में, दक्षिण बिहार के 17 जिले, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई- ये 17 जिले हैं महोदय, जहां सुखाड़ पड़ता है महोदय । हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को जिनके प्रयास से आज 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की है । हम सर्वे करा रहे हैं और हमने तय किया है कि रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅार डेवलपमेंट फंड के माध्यम से आर.आई.डी.एफ. के माध्यम से, नाबार्ड के यहां पर जो वरीय अधिकारी हैं, उनसे हमने बात की है, आपको कृषि में खर्च करना है । हमने आग्रह किया है, हम विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठकर बात किये है । महोदय, हमने कहा है कि दक्षिण बिहार के उन जिलों में 332 और प्रोजेक्ट हैं जिनपर काम करने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में हम सुखाड़ वाले जिले की बात कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिये, उधर भी हम आ रहे हैं । पानी का संकट है, जल संचय की जो योजना है, वह बहुत अच्छी योजना है, हमने अधिकारियों से बात की है कि क्या इसका रास्ता है ? कैसे इसको बढ़ाया जाय ? तो जल छाजन की जो योजना है, बड़े पैमाने पर तालाब, चेक डैम, नहर और जल का संचय हम कर रहे हैं और काफी अच्छे परिणाम आ रहे हैं, गांव का पानी जो हमारा है, उसका टेबुल हमारा ठीक हो गया है, सिंचाई के काम में आ रहा है । हम मछली पालन शुरू करेंगे । इस तरह महोदय, दूसरा यह हमने तय किया है कि हमारे पास आने वाले समय में हमारी बिहार की सरकार है, पैसों की कमी नहीं है, बिहार के साथ-साथ नरेन्द्र भाई मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़े हैं, खजाना खोल कर खड़े हैं, जो पैसे की जरूरत होगी, पैसे की कमी नहीं होगी । आने वाले समय में हमारा फर्स्ट सप्लेमेंट्री आने वाला है, हमने योजना विभाग से मांग किया है कि हमारी कैबिनेट ने, हमने जो 21 हजार करोड़ पास किया है हमने डिमान्ड किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सहयोग से निश्चित तौर पर आने वाले समय में कृषि का बजट का हमारा बड़ा होगा, ऐसा हमारा प्रयास होगा । साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि अभी तक महोदय जो 12 विभाग है, यह 12 विभाग को मिलाकर ऐतिहासिक काम जो की है महोदय, पशु एवं मत्स्य संसाधान विभाग 5,785 करोड़, ग्रामीण कार्य विभाग 52,935 करोड़, लघु जल संसाधन 25,777 करोड़, जल संसाधन विभाग 26,614 करोड़, सहकारिता में 6,131 करोड़, गन्ना में 1,090 करोड़, रेवेन्यू एवं लैंड रिफार्म में 432 करोड़, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण में 2,262 करोड़, उर्जा में 7,070 करोड़, पर्यावरण एवं वन में हमारा 2435 करोड़ और खाद्य प्रस्संकरण में 4,588 करोड़ इतना बड़ा बजट बना महोदय, आने वाले पांच वर्षो में सरकार का जो प्रयास है महोदय । दूसरा महोदय, हम यांत्रिकरण के बारे में बतलाना चाहते हैं । महोदय, हम चाहते हैं किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच कर रहे हैं, उनका लागत कमे, जब खाद का प्रयोग कम होगा, स्वाभाविक है कि उसका लाभ किसानों भाइयों को होगा । चालू वित्तीय वर्ष में हमारे पास 180 करोड़ का बजट था और 180 करोड़ में लगभग 1 लाख 30 हजार जाकर पड़ा महोदय और 1 लाख से अधिक लोगों को परमिट जारी किया, हमारी लगभग 40 प्रतिशत राशि खर्च हो चुकी है, हम प्रयास कर रहे है और हमने तय किया है हम अक्टूबर से जो कृषि यंत्र का मेला लगाते थे और उनसे आवेदन लेते थे, अब हमने फैसला किया हैं कि अक्टूबर से नहीं

1 अप्रील से हम किसानों से आवेदन लेंगे, सालो भर हमारा दरवाजा खुला रहेगा, किसान भाई आयेंगे, ऑन लाईन उनको अप्लाई करना है, सब्सिडाईज रेट पर, हमारे पास 71 तरह के कृषि यंत्र हैं, यह सुविधा उनको उपलब्ध कराने का काम करेंगे महोदय । साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि भारत सरकार ने महोदय कस्टम हायरिंग योजना के संबंध में राशि उपलब्ध कराने का काम किया था, 87 योजनाओं का हमने प्रस्ताव भेजा है, प्रक्रिया में है महोदय और हमलोग चाहते हैं कि आने वाले समय में हम राज्य के किसानों को कृषि यांत्रिकीकरण के माध्यम से हमारा प्लान है, हम फार्मर, प्रोड्यूसर ऑर्गनाईजेशन बनाने जा रहे हैं । राज्य के जो 534 प्रखंड हैं, हम किसानों को सामूहिक करने जा रहे हैं और समूह के माध्यम से कृषि यंत्र लगाया जायेगा और 10 लाख तक में 8 लाख सब्सिडी है । 10 लाख से 25 लाख पर 40 परसेंट सब्सिडी है और 25 लाख से 50 लाख तक 40 फीसदी सब्सिडी है । महोदय, हमारा किसान समूह में नहीं है कि वह मंहगा यंत्र नहीं खरीद सकेगा और उनको यंत्र की आवश्ययकता है, बदलते परिवेश में दुनियां बदल रही है, नये-नये तकनीक आ रहे हैं, नये-नये रिसर्च हो रहे हैं, हम नये तरीके से, आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम किसानों को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं और इसीलिये हमने तय किया है कि अगले वित्तीय वर्ष में हम कृषि यंत्र बैंक बनायेंगे और लक्ष्य जो हमारा होगा, वह पंचायतों तक जायेगा । हर पंचायत में, हर प्रखंड में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना करके किसानों को हर तरह के कृषि यंत्र सुविधा उपलब्ध करायेंगे । साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिये समेकित कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं । हमने कहा कि खेत में मछली पालन करो, मुर्गी पालन भी होगा, मछली पालन भी होगा, मधुमक्खी पालन भी होगा, गौपालन होगा, चावल और गेहूं से हमारी आमदनी बढ़नेवाली नहीं है । हम किसानों को चावल गेहूं के साथ-साथ हम प्रयास कर रहे हैं, हम किसानों को ट्रेनिंग दे रहे है, हमारा महोदय लक्ष्य था ट्रेनिंग देने का और हमें बताते हुये खुशी हो रही है कि पूरे राज्य में हमने किसानों को ट्रेनिंग दिया है और महोदय किसान ट्रेंड हो रहे हैं । 23 पाठ्यक्रमों- मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, वर्मी कम्पोस्ट के बारे में, मछली पालन के बारे में, गो-पालन के बारे में, बकरी पालन के बारे में इस तरह से हमारा लगातार प्रयास हो रहा है कि आनेवाले समय में हम किसानों को हम मजबूत करना चाहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े और किसान अपने पैरों पर खड़ा हों, यह कृषि विभाग का लगातार प्रयास है और महोदय, हम कहना चाहते हैं कि किसानों के लिये हमने जो प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, 2017-18 चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख 42 हजार 595 किसानों को हमने ट्रेनिंग दिया है । इस प्रकार कृषि संबद्ध क्षेत्र में कुल 7,773 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है और राज्य के जिलों के अंदर और राज्य के बाहर हम किसानों को 68,541 किसानों को परिभ्रमण कराने का काम किया है । कृषि एवं कृषि संबद्ध क्षेत्रों के किसानों को नवीनतम कृषि की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु 1655 किसान पाठशाला का आयोजन किया है । किसानों को स्वावलंबी बनाने हेतु 2363 किसान समूह का गठन किया है और महिलाओं की बात कर रहे हैं, हमलोग कम-से-कम 33 परसेंट महिलाओं को उसमें शामिल कर रहे हैं और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित परिवार के लोग हैं, उनको 17 परसेंट देने जा रहे हैं । जिस तरह हम समूह बनाने का काम कर रहे हैं । साथ ही साथ महोदय, हमारा प्रयास है जिस तरह से मौसम बदल रहे हैं ।

क्रमश :

टर्न-20/ज्योति/07-03-2018

क्रमशः

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : जिसतरह से मौसम बदल रहा है । बदलते मौसम के हिसाब से हम चल रहे हैं और हमलोगों ने तय किया है कि किसानों को सही समय पर मौसम, वर्षा, आर्द्रता आदि की जानकारी देते हुए प्रखंड स्तर पर टेलीमैट्रिक वेदर स्टेशन पंचायत स्तर पर वर्षा मापक यंत्र स्थापित किया जा रहा है और चालू वित्त वर्ष में पायलट प्रोजेक्ट के तहत महोदय, हमलोगों ने पूर्वी चम्पारण, सुपौल, नालन्दा, को शामिल किया है । किसानों को समय से पहले हम जानकारी देंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व कृषि विभाग आगे बढ़ रहा है और हमने किसानों के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन से जोड़ने का काम किया है तो इसतरह हमारा प्रयास है कि राज्य में हम किसानों के बेहतर सिंचाई की उपलब्ध करायें । हमने प्लान किया है जिले में डिस्ट्रीक्ट एरीगेशन प्लान बना रहे हैं लेकिन पंचायत में किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक और कृषि पदाधिकारी को आदेश दिया है कि मिलकर एक योजना बनाईये उसको हम सिंचाई विभाग द्वारा और जिला स्तर पर जॉच कराने का काम करेंगे । आज के मौके पर हम चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारा जो राज्य के अंदर में जो हमने तय किया है, जो हमारा कृषि रोड मैप है, हम कृषि रोड मैप मे हमलोगों ने तय किया है कि कृषि रोड में प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार चाहती है और प्रथम फेज में हमलोगों ने राज्य के 9 जिलों में पटना से भागलपुर तक गंगा के किनारे दोनों तरफ सब्जी की खेती में हम जैविक खेती के माध्यम से किसान भाई बहन को इनपुट्स सब्सिडी देने जा रहे हैं और कहना चाहते हैं कि जाने-अनजाने में हमारे किसानों ने खेतों में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाईयों के प्रयोग करने से हमारे लोगों का स्वास्थ्य जिसतरह से खराब हुआ उसका असर पड़ा तो आने वाले समय में राज्य सरकार का प्रयास है कि हम जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 2 हजार एकड़ में हमलोगों ने जैविक खेती करने की योजना बनायी है और अगले वित्तीय वर्ष में 25 हजार एकड़ में हम जैविक खेती बिहार के नेशनल हाई वे किनारे स्टेट हाईवे के किनारे किसान जो खेती करते हैं, हमारा प्रयास रहेगा साथ ही साथ महोदय, हम कहना चाहते हैं कि राज्य के जो 38 जिले हैं, 38 जिले में, हर जिले में एक जैविक ग्राम बनाया जायेगा और जैविक ग्राम के माध्यम से हमारा प्रयास है हम जैविक डेमो के माध्यम से किसानों में जागृति लाना चाहते हैं । यह राज्य सरकार की पहल है, मुझे प्रसन्नता है कि हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी कई जिले में गए थे और मैं भी साथ में था और लोग जैविक सब्जियॉ लाकर स्टेज पर दे रहे थे । यानी पहले से ही बड़े पैमाने पर जैविक खेती यहॉ पर कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर हमारा प्रयास होगा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने की जो सरकार की योजना है वह निश्चित तौर पर ससमय जमीन पर आये और आने वाले समय में अप्रील में बिहार के लोगों को हमने सिक्किम सरकार के साथ, सिक्किम की जो प्रमाणीकरण एजेन्सी है, उसके साथ राज्य सरकार का कृषि विभाग प्रमाणीकरण एजेन्सी के साथ एम.ओ.यू. किया है ताकि तीन वर्षों के लिए ताकि आने वाले समय में बिहार ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल है कि देश के हर थाली में

बिहार का व्यंजन हर थाल में हो । माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है कि किसानों की आमदनी दुगुनी हो, उसके लिए स्वायल हेल्थ कार्ड पर हम जोर दे रहे हैं । किसानों को अलग से ट्रेनिंग देने का मैं काम कर रहा हूँ । समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना चाहते हैं । राज्य को हम खेतों को हम यांत्रिकरण के माध्यम से कम समय में आधुनिक तरीके से हम वैज्ञानिक तरीके से खेती को बढ़ाना चाहते हैं । कृषि समन्वयक है जिसके संबंध में आपने भी चिंता व्यक्त की थी और हमारी सरकार को कहने की जरुरत नहीं है स्वत: हर काम हो रहा है और अभी तक महोदय, मुझे खुशी हो रही है कि 3168 कृषि स्नातक समन्वयक ज्वाईन कर चुके हैं, काम कर रहे हैं और शेष जो बच गए है उसकी प्रक्रिया अपनायी जा रही है और जल्द इनकी भी नियुक्ति की जायेगी । किसान सलाहकार जो हमारे थे उनकी राशि 8 हजार से बढ़ाकर 12 हजार हमलोगों ने करने का काम किया है । सरकार की चिंता है, सरकार चाहती है कि निश्चित तौर पर जो काम करने वाले हमारे साथ जो हमारे किसान सलाहकार हैं और हमारे साथ साथ जो कृषि समन्वयक हैं उनकी भी चिन्ता हमारी सरकार कर रही है । साथ ही साथ उद्यान के क्षेत्र में, हौर्टिकल्चर में यहाँ पर लोगों ने चिन्ता व्यक्त की थी मक्का के बारे में, हम भी उत्तर बिहार के दौरे पर गए थे , मुझे भी जानकारी मिली समाचारपत्रों में देखा । आज माननीय सदस्यों ने कहा है कि मक्के की खेती में जो बाली में दाना महोदय नहीं आया है हमने विभाग को आदेश दिया है और कमिटी बना दी है हमारे अधिकारी जॉच कर रहे हैं जॉच के बाद कोई दोषी पाये जायेंगे बख्शा नहीं जायेगा वैसे बीज वालों के खिलाफ जिनके द्वारा नक्ली बीज दिया गया हो इसकी चिन्ता व्यक्त माननीय सदस्य कर रहे थे तो हमारे विभाग के अधिकारी जॉच करेंगे और जॉच का परिणाम जब आयेगा तो कोई बख्शा नीं जायेगा वैसे लोगों के खिलाफ जो किसानों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जायेगा । उत्तर बिहार में जब 21 जिलों में बाढ़ आयी और बाढ़ के बाद हमने कृषि विभाग में कृषि समन्वयकों और सलाहकार को कहा कि पानी निकलने के बाद सर्वे कराईये और पानी रिसीड करने के बाद एक महीने के अंदर में हम लोगों ने सर्वे कराकर जिला पदाधिकारी के माध्यम से आपदा प्रबंधन को भेजने का काम किया । मुझे बताते हुए खुशी हो रही है । 894 करोड़ महोदय, 17 अक्तूबर को दीपावली के एक दिन पहले महोदय, कैबिनेट से पास कराकर - बिहार में सभी जिलों में हमें जानकारी मिली है 75 परसेंट किसानों के खाते में राशि चली गयी है और जो शेष राशि बची है हमें आशा है कि निश्चित तौर पर इस महीने तक किसानों के खाते में जो फसलों का नुकसान हुआ है राज्य सरकार ने राशि भेजी है, उसे खाते में भेजने का प्रयास किया जायेगा । कृषि विभाग का प्रयास है । दूसरी तरफ प्रयास कर रहे हैं किसानों के लिए बाजार । घुमते हुए लोग कहते हैं, चिन्ता मत कीजिये अभी सहकारिता विभाग के द्वारा महोदय, औरगेनिक खेती हमलोग करने जा रहे हैं सब्जी का, सहकारिता विभाग से आदेश मिला है कोऔपरेटिव बनाया जा रहा है, कोऔपरेटिव के माध्यम से हर तरह की उनको मदद दी जायेगी और हमारा कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण 54 जो है, जर्जर स्थिति में आ गया था उसको भी हमलोग ठीक करने जा रहे हैं । उसकी चहारदिवारी , वहाँ पर सड़क, ड्रेन- हमलोगों ने दरभंगा में स्वीकृत कर दिया है और पूर्णिया का और जिलों का आ रहा है तो सरकार का

प्रयास है 72 करोड़ का बजट हमारा चालू वित्तीय वर्ष में है और अगला 80 करोड़ का है उसके अलावा दो सौ करोड़ की राशि कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण के पास पड़ी हुई है तो हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में राज्य के 54 कृषि उत्पाद बाजार प्रांगण है उसको बेहतर बनाकर किसानों को हम बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे । भंडारण की बात आती है कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है उसमें परिस्थिति आती है तो सरकार के स्तर पर महोदय, निश्चित तौर पर कृषि रोड मैप में महोदय, इन सारी बातों की व्यवस्था की गयी है कि आने वाले समय में हम भंडारण की बेहतर व्यवस्था करेंगे । साथ ही साथ राज्य में जो स्पेशल क्रौप है, 38 जिले में स्पेशल क्रौप पहचान की गयी है उसपर भी हमलोग काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अब तो कटौती वापस लेने वाले दिख नहीं रहे हैं हम तो आग्रह करेंगे महोदय सभी माननीय सदस्यों से कि कृषि विभाग के द्वारा जो बजट पेश किया गया है और एक लास्ट में गन्ना का अपना रह गया था । उनके बारे में दो शब्द कहना चाहते हैं । 18-19 में सरकार द्वारा अनुदान देने का प्रतिफल है कि महोदय 25 परसेंट गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हुयी है । एक मात्र गन्ना कैश क्रौप हमारा है गन्ना कृषकों के प्रति सरकार गंभीर है । सरकार द्वारा नये प्रभेद के गन्ना लगाने वाले कृषकों को सरकार अनुदान दे रही है । गन्ना कृषकों को गन्ना के प्रति काफी अभिरुचि बढ़ी है, अगले वित्तीय वर्ष में गन्ना का प्राईस होगा - गन्ना अप्रील तक हो रहा है, मई तक किया जायेगा । बिचौलिए का खात्मा हो चुका है, गन्ना किसान काफी खुश है और बड़े पैमाने पर हमारे राज्य में गन्ना किसान हैं गन्ना की खेती करने का काम कर रहे हैं और अंत में हम आग्रह करेंगे कि हमने जो बजट पेश किया है, हमारे सारे सत्तारुढ़ दल और विपक्ष के लोगों ने बहस किया है इसको सर्व सम्मति से पारित कराने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो बचा हुआ रह गया है, समय कम था, हम दे देते हैं प्रोसिडिंग्स का पार्ट बन जाय ।

अध्यक्ष :ठीक है, माननीय मंत्री जी जो सदन पटल पर दस्तावेज रखेंगे वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

टर्न-21/07.3.2018/बिपिन

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री भोला यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/-से घटाई जाए ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''कृषि विभाग के सम्बन्ध में 31मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 27,49,77,93,000/- (सत्ताइस अरब उनचास करोड़ सतहत्तर लाख तिरानवे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 07 मार्च, 2018 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 21(इक्कीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार दिनांक 08 मार्च, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मशहूर किसान कवि घाघ ने कहा है **''उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान''** महोदय प्राचीन काल से ही कृषि को सबसे उत्तम जीविका का साधन माना गया है। खेती सबसे सम्माननीय कार्य माना गया है। परन्तु वर्त्तमान में जलवायु परिवर्त्तन के परिपेक्ष्य तथा जनसंख्या के बढ़ते दबाव से कृषि योग्य भूमि में कमी आयी है। इन परिस्थितियों के बीच वर्त्तमान की केन्द्र एवं राज्य की सरकार टिकाऊ खेती के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ सतत् प्रयत्नशील है। देश में पूर्ववर्त्ती सरकारों द्वारा कृषि के संधारणीय विकास यानि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए चरणबद्ध ढंग से कोई समेकित कार्यक्रम नहीं बनाया गया, जिसके कारण कृषि के समक्ष कुछ चुनौतियाँ उत्पन्न हुई है। महोदय, बिहार संभवतः देश का पहला राज्य है, जहाँ कृषि के चरणबद्ध विकास के लिए कृषि रोड मैप बनाया गया है, और इसके लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूँ। साथ ही, कृषि के क्षेत्र में बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के लिये माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारी सरकार कृषि को पुनः सम्माननीय एवं लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है।

महोदय, कृषि के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि हमारा जीवन ही कृषि पर आधारित है। महोदय, कृषि का विकास ही समग्र विकास की कुँजी है। परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि पर्यावरण

को नुकसान पहुँचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल और मानवशक्ति की उत्पादक क्षमता का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाये। बिहार में कृषि के विकास से ही आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

महोदय यह हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति ने बिहार को बहुत ही उपजाऊ मिट्टी और प्रचूर जल संसाधनों का वरदान दिया है। साथ ही, यहाँ कृषि जलवायु की विशाल विविधता है, जो बागबानी तथा औषधीय पौधों सहित बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती के लिये काफी अनुकुल है। बिहार गंगा की तराई में बसा है। यहाँ भूगर्भीय जल काफी मात्रा में है। सब्जियों की पैदावार में हम सबसे आगे हैं। मखाना, लीची पैदा करने में भी हम सबसे आगे हैं। अनानास, आम, केला, अमरूद, गन्ना, जूट आदि पैदा करने में भी हमारी श्रेष्ठता स्थापित है। जरूरत है तो बस इसके लिये बेहतर बाजार की व्यवस्था करने की।

महोदय, राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। कृषि का क्षेत्र सभी वर्ग के लोगों को रोजगार मुहैया कराता है, इसलिये यह बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

महोदय, दूसरे किसी भी प्रदेश की अपेक्षा बिहार के लिए कृषि सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की 76 (छिहत्तर) प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है और यहाँ की कृषि जी.डी.पी. राज्य के जी.डी.पी. का पाँचवाँ हिस्सा है। राज्य में कुल 13 (तेरह) मिलीयन कृषि परिवार के पास 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन है। जहाँ देश में औसतन 42 (बेयालिस)

प्रतिशत जमीन पर खेती होती है वहीं बिहार में 60 (साठ) प्रतिशत जमीन पर खेती होती है।

आज जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है और हमारा बिहार भी प्राकृतिक आपदाओं से अछूता नहीं है यहाँ के 90 प्रतिशत जिलों को सुखाड़ एवं बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद हमारे अन्नदाता किसान दिन रात मेहनत कर राज्य को उन्नति की शिखर तक पहुँचाने के लिए निःस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं यह राष्ट्रभक्ति की पराकाष्ठा है, महोदय।

आसमान पर नजर हमेशा, वो आंधी तुफां सब सहते हैं।
खेतों में हरियाली आये, दिन रात लगे वो रहते हैं।।
मेहनत कर वो अन्न उगाते, पेट सभी का भरते हैं।
वो है मसीहा मेहनत का, उनको किसान हम कहते हैं।।

महोदय, इन परिस्थितियों के बीच राज्य में कृषि के विकास की महत्ता को देखते हुए सरकार द्वारा कृषि रोड मैप बनाया गया है। इस रोड मैप में चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार कर कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि रोड मैप में फसल एवं बागवानी के साथ–साथ अन्य कार्यक्रमों को मिलाकर एक समग्र योजना बनायी गयी है। कृषि से संबंधित सिंचाई, बिजली, सहकारिता, ग्रामीण सड़क, खाद्य प्रसंस्करण सहित कृषि आधारित उद्योग के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समग्र योजना को लागू किया गया है। वर्ष 2008 में पहली कृषि रोड मैप की शुरूआत की गयी तथा वर्ष

2012 मे दूसरे कृषि रोड मैप एवं 2017 से तीसरे कृषि रोड मैप को लागू किया जा रहा है।

महोदय, कृषि रोड मैप कार्यक्रमों पर 2021–22 तक 12 विभागों के द्वारा कृषि के विकास के लिये 1.54 लाख करोड़ खर्च किये जायेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल के अनुरुप हमने संकल्प लिया है कि प्रत्येक भारतीय के थाल में बिहार का एक व्यंजन पहुँचायेंगे।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा स्वयं दिनांक 09 नवम्बर, 2017 को तीसरे कृषि रोड मैप का शुभारम्भ किया गया है।

महोदय, कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों के फलस्वरूप कई महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की गई हैं। वर्ष 2012 में चावल उत्पादन तथा वर्ष 2013 में गेहूँ तथा 2016 में मक्का के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। धान की उत्पादकता में 224 (दो सौ चौबीस) क्विं० प्रति हेक्टेयर तथा आलू की उत्पादकता में 729 (सात सौ उनतीस) क्विं० प्रति हेक्टेयर का विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ। वर्ष 2017–18 में कुल खाद्यान्न में रिकार्ड उत्पादन हुआ है। विपरीत मौसम की परिस्थिति में सरकार के सहयोग से राज्य के किसानों ने अपने अदम्य साहस एवं लगनशीलता से यह कीर्तिमान स्थापित किया है, इसके लिए मैं राज्य के अन्नदाता किसानों को कोटि–कोटि नमन करता हूँ। साथ ही, उनके लिए मैं दो पक्तियाँ कहना चाहूँगा।

"चीर के जमीन को, मैं उम्मीद बोता हूँ।
मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ।।"

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य के विकास को गति प्रदान करने, विशेषकर बिहार राज्य को, भारत ही नहीं विश्व मानचित्र में एक अलग पहचान देने का प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार 'न्याय के साथ विकास' का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने का संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

वर्ष 2018–19 के केन्द्रीय बजट में कृषि को जो प्रधानता मिली है, उसके लिए मैं बिहार के किसानों की तरफ से तथा अपने विभाग के तरफ से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत सरकार ने किसानों की चिर लम्बित माँगों को पूरा किया है। देश के किसानों को उनके लागत का डेढ़ गुणा न्यूनत्तम समर्थन मूल्य देने का केन्द्र सरकार का संकल्प ऐतिहासिक है। इतना ही नहीं महोदय, वर्ष 2018–19 के केन्द्रीय बजट में फसल बीमा, स्वायल हेल्थ कार्ड, कृषि यांत्रिकरण, सूक्ष्म सिंचाई, शुष्क खेती के विकास, डेयरी के विकास तथा मत्स्यपालन के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था की गयी है।

महोदय, केन्द्र सरकार की योजनाओं एवं प्राथमिकताओं के साथ कदम–से–कदम मिलाकर राज्य सरकार कृषि विकास कार्यक्रमों को पूरी तत्परता से लागू कर रही है।

<u>खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन :</u>

महोदय, वर्ष 2017 कृषि के क्षेत्र में उपलब्धियों का वर्ष रहा है। राज्य में 185.6 लाख मिट्रीक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इस वर्ष मक्का का उत्पादन भी 38 लाख मिट्रीक टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा है। मक्का उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए चुना गया है।

<u>कृषि समन्वयकों की स्थायी नियुक्ति :</u>

महोदय, वर्ष 2017 में 3168 कृषि स्नातकों को कृषि समन्वयक के स्थायी पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य में इतनी बड़ी संख्या में कृषि स्नातकों की नियुक्ति पहली बार हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में राज्य के कृषि को नई दिशा प्राप्त होगी।

<u>किसान सलाहकारों के मानदेय में वृद्धि :</u>

महोदय, पंचायत स्तर पर कार्यरत किसान सलाहकारों का मानदेय भी 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है। सरकार के इन जनहितकारी कार्यों से कृषि के क्षेत्र में एक सकारात्मक वातावरण का संचार हुआ है।

कृषि का समग्र विकास :

महोदय, कृषि रोड मैप के परिणामस्वरूप फसलों के साथ ही दूध, मछली, मांस का उत्पादन बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़क का जाल बिछा है। नौबतपुर में अलग कृषि फीडर का काम पूरा हुआ है। महोदय, विद्यालय के स्तर पर आई.एस.सी.(एजी.) की पढ़ाई शुरू हुई है। मक्का तथा चावल प्रसंस्करण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिली है। हरियाली मिशन कार्यक्रम के माध्यम से पिछले पाँच वर्षों में 18 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाये गये हैं।

महोदय, राज्य में खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा तथा किसानों की आमदनी को दोगुना करने के संकल्प के साथ तीसरा कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। महोदय, इसके लिए अनाज, दाल, तेलहन, मांस, मछली, दूध, अण्डा के पर्याप्त उत्पादन के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाये गये हैं। इतना ही नहीं महोदय किसानों के उत्पादन को बेहतर बाजार देने के लिए तथा भंडारण एवं प्रसंस्करण के लिए कार्यक्रम बनाये गये हैं। किसानों को सस्ते दर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जहाँ एक तरफ निजी नलकूप की योजना बनायी गयी है, वहीं अलग कृषि फीडर के माध्यम से 7 लाख 94 हजार नलकूप को ऊर्जान्वित करने के कार्यक्रम भी निर्धारित किये गये हैं।

जैविक कोरिडोर योजना :

कृषि रोड मैप को लागू करने के लिए कृषि विभाग द्वारा विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। कृषि रोड मैप 2017–22 में जैविक खेती योजना पर विशेष बल दिया गया है। वर्तमान वर्ष में जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम में पटना से भागलपुर तक के गंगा किनारे पड़ने वाले गाँव तथा दनियावाँ से बिहारशरीफ तक के राष्ट्रीय सड़क के किनारे पड़ने वाले गाँव को जैविक कोरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह योजना 09 (नौ) जिलों, यथा– पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, लखीसराय, खगड़िया एवं मुंगेर में कार्यान्वित की जा रही है तथा आगामी वर्ष में 09 (नौ) जिलों के अतिरिक्त गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर जिला को भी शामिल किया जायेगा, जिससे जैविक कोरिडोर के रूप में जैविक खेती विकसित हो सके। इसके साथ–साथ प्रत्येक जिले में एक जैविक ग्राम का चयन किया गया है, जिसमें किसानों को अधिक–से–अधिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई का लाभ दिया जा रहा है। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु इस वर्ष से प्रमाणीकरण की योजना चलायी जा रही है, जिससे किसानों को उनके जैविक उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। बिहार में जैविक खेती के प्रमाणीकरण करने हेतु बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑरगेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना को प्राधिकृत किया गया है तथा इसके लिए सिक्किम राज्य के प्रमाणीकरण संस्था के साथ 1 नवम्बर, 2017 को एम०ओ०यू० किया गया है। वर्ष 2017–18 में जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित गाँव के अतिरिक्त अन्य इच्छुक किसानों के भी जैविक खेती को निःशुल्क प्रमाणीकरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

स्वायल हेल्थ कार्ड :

महोदय, टिकाऊ खेती के लिए मृदा का स्वस्थ होना आवश्यक है। मृदा के स्वास्थ्य की जाँच मिट्टी परीक्षण के द्वारा की जाती है। इसके लिए सभी जिलों में मिट्टी जाँच प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं, जहाँ किसानों के खेत से संग्रहित मिट्टी के नमूने निःशुल्क जाँच किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रमंडल में एक–एक यानी कुल 9 चलन्त मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। वर्ष 2017–18 में अभी तक 6,54,389 मिट्टी नमूने वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 5,83,062 मिट्टी नमूनों का संकलन किया गया है, जिनमें 3,25,624 नमूनों को विश्लेषित कर 10,67,336 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किसानों के बीच किया गया है।

कृषि यांत्रिकरण :

महोदय, कृषि यांत्रिकरण योजना में पारदर्शिता लाने के लिए यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य में इच्छुक कृषकों द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑन लाईन आवेदन किया जा सकता है। किसानों को अनुदान की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 1.84 लाख से अधिक ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया गया है, जिसके नियमानुसार जाँचोपरांत 1.30 लाख से अधिक स्वीकृति पत्र निर्गत किये गये हैं।

केन्द्र प्रायोजित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष

2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत 10.00 लाख, 25.00 लाख एवं 40.00 लाख तक की लागत से कस्टम हायरिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक तथा 80.00 लाख रूपये की लागत वाले दो हाईटेक हब की स्थापना किया जाना है। उक्त सभी कृषि यंत्र बैंक/हाईटेक हब की स्थापना पर 40 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इसके अलावा चयनित ग्रामों में 10.00 लाख रूपये तक की लागत से कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जा रही है, जिसमें 80 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

किसानों का प्रशिक्षण :

महोदय, आत्मा एवं बामेती द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में अभी तक कुल 242595 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। इसी प्रकार से कृषि एवं कृषि के संबद्ध क्षेत्रों में कुल 7773 प्रत्यक्षण का आयोजन किया गया है। राज्य/जिला के अन्दर तथा राज्य के बाहर कुल 68541 किसानों को परिभ्रमण कराया गया है। कृषि एवं कृषि के संबद्ध क्षेत्रों में किसानों को नवीनत्तम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कुल 1655 किसान पाठशाला का आयोजन किया गया है। किसानों को सुदृढ़ एवं स्वाबलम्बी बनाने हेतु कुल 2363 किसान हित समूहों का गठन किया गया है तथा महिला किसानों को स्वाबलम्बी बनाने हेतु कुल 648 खाद्य सुरक्षा समूह का गठन किया गया है। इसी प्रकार से किसानों के स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु कुल 774 किसान गोष्ठी एवं कुल 35 किसान वैज्ञानिक वार्तालाप का आयोजन किया गया है।

किसान चौपाल :

महोदय, किसान चौपाल कार्यक्रम में अभी तक राज्य के सभी पंचायतों, यथा–कुल 8405 पंचायतों को आच्छादित किया गया है, जिसमें कुल 500097 किसानों ने भाग लिया है तथा कुल 4890 सुझाव किसानों से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सुझावों को योजनाओं के कार्यान्वयन सम्मिलित करने की व्यवस्था की जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष में खरीफ, रबी तथा गरमा मौसम के पूर्व राज्य के सभी पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन किया जायेगा।

किसानों का कौशल विकास :

महोदय, कौशल विकास मिशन योजना बिहार कौशल विकास मिशन अंतर्गत कृषि प्रक्षेत्र में कुल 23 पाठ्यक्रमों में पुरूष/महिला किसान/ग्रामीण युवा/युवतियों को 77 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में अभी तक कुल 3815 महिलाओं/पुरूषों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।

पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय :

महोदय, अभी तक किसानों को योजनाओं की जानकारी एवं उसका लाभ लेने के लिए जिला एवं प्रखंडों का चक्कर लगाना पड़ता था। सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के सभी पंचायतों में कृषि कार्यालय खोले जायेंगे जहाँ नियमित रुप से कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान कराने हेतु उपलब्ध रहेंगे। हमारा प्रयास होगा कि किसान हम तक नहीं हम किसानों के द्वार तक पहुँचे।

कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) :

महोदय, राज्य में किसानों को सामूहिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने तय किया है कि प्रथम चरण में राज्य के सभी 534 प्रखंडों में एक–एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाईजेशन ;थ्च्व्द्ध कंपनी बनाया जायेगा। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मार्च, 2018 तक सभी एफ०पी०ओ० आकार ले लेगा। इसके बाद पंचायत स्तर पर एफ०पी०ओ० का गठन किया जायेगा। जब लोग समूह में खेती करेंगे, तो उनके उत्पादों के लिए बाजार स्वयं उनके पास आयेगा तथा उनके उत्पादों को उच्चत्तर मूल्य मिल सकेगा। इन किसान समूहों को सरकार कृषि की सभी योजनाओं का लाभ भी प्रदान करेगी।

जलवायु परिवर्त्तन :

महोदय, राज्य में जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार के समन्वय से 25 करोड़ की परियोजना कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन संभाग, भारत सरकार द्वारा कुल 23 करोड़ 11 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसकी आधी राशि विमुक्त कर दी गई है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है।

टेलीमेट्रीक वेदर स्टेशन :

महोदय, किसानों को सही समय पर मौसम, वर्षा, आर्द्रता आदि की जानकारी देने हेतु प्रखंड स्तर पर टेलीमेट्रीक वेदर स्टेशन एवं पंचायत स्तर पर वर्षा मापक यंत्र स्थापित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में पायलट प्रोजेक्ट के रुप में राज्य के पाँच जिलों, यथा–पूर्वी चम्पारण, सुपौल, नालन्दा, गया तथा अरवल जिले में इसे स्थापित किया जा रहा है। अगले चरण में राज्य के सभी जिलों में इसकी स्थापना की जायेगी।

बागवानी विकास :

महोदय, राज्य में बागवानी के विकास हेतु नये बागों की स्थापना के लिए किसानों को सहायता दी जा रही है। वर्ष 2017–18 में कुल 4,86,328 आम पौधा, 51,507 अमरूद पौधा, 1,52,500 लीची पौधा, 25,490 आँवला पौधा, 52,600 बेल पौधा, 26,025 कटहल पौधा, 98,300 शरीफा पौधा एवं 52,500 जामुन पौधा का उत्पादन किया गया है, जिसे योजनाओं के तहत् कृषकों को उपलब्ध कराया गया। राज्य में आम, लीची, केला, पपीता एवं अन्य बागवानी फसलों की उन्नत तकनीक का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। फल–सब्जी के संरक्षित खेती को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। बागवानी विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के साथ–साथ मुख्यमंत्री बागवानी मिशन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

राज्य में प्रत्येक जिला के लिए विशेष फसलों, जैसे–लीची, आम, मखाना, पान, मशाला, अनानास, जूट आदि लगभग 38 फसलों का चयन कर इसके प्रोत्साहन हेतु योजना बनाई गई है। इससे प्रत्येक जिला एक हब के रूप

में विकसित होगा, जिससे उसके विपणन एवं प्रसंस्करण में काफी सहुलियत होगी।

वर्ष 2018–19 में 60 लाख जी०–9 प्रभेद के टिश्यू कल्चर केले के पौधे कृषकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। मधुमक्खीपालन को बढ़ावा देने के लिए 50,000 मधुमक्खी बक्से राज्य के कृषकों को 2018–19 में उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने एवं प्रत्येक जिले में एक पहचानित उद्यानिक फसलों के विकास तथा बागों में अन्तर्वर्त्ती फसल, संरक्षित खेती, विपणन हेतु आधारभूत संरचना विकास, मसाला फसलों के विकास इत्यादि अवयवों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की महत्त्वाकांक्षी योजना तैयार किया गया है। राज्य में जैविक सब्जी उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु इनपुट अनुदान कार्यक्रम की योजना चलायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के जैविक कोरिडोर हेतु चयनित जिलों के अलावा अन्य मुख्य सब्जी उत्पादक जिलों में कराया जायेगा। सिंचाई जल के बचत हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per drop more crop) तैयार की जा रही है। इस योजना अन्तर्गत कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं सब्जियों के अन्तर्गत खेती में पारम्परिक सिंचाई व्यवस्था से हटकर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का इस्तेमाल हेतु कार्यान्वित किया जायेगा। जिसके तहत् किसानों को 75 प्रतिशत अनुदानित दर पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के संयंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रत्येक जिला के लिए वहाँ की सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार डिस्ट्रीक्ट इरीगेशन प्लान तैयार कराया गया है।

भूमि एवं जल संरक्षण :

भूमि संरक्षण की राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017–18 में भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित 731 विभिन्न आकार के संरचनाओं के निर्माण/जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है एवं 680 हेक्टर क्षेत्र में पौधा रोपण तथा फार्म वंडिंग आदि का कार्य कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत 6525 विभिन्न आकार के संरचना का निर्माण/मरम्मति आदि का कार्य तथा 973 हे0 क्षेत्र में पौधा रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जलछाजन विकास अन्तर्गत (समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम) मुख्यतः जलछाजन के कार्य चरण में 491 विभिन्न जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसमें परियोजना क्षेत्र अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रम, प्रवेश बिन्दु क्रिया–कलाप एवं जिला स्तर पर विभिन्न कर्मियों/लाभान्वित समूहों को प्रशिक्षण दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में जलछाजन विकास योजनान्तर्गत 4122 विभिन्न आकार के संरचनाओं का निर्माण/मरम्मति आदि कार्य तथा 43,513 हे० क्षेत्र में पौधा रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जलछाजन योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्षा जल का अधिक–से–अधिक संरक्षण होगा, जिससे कृषि कार्य में सहयोग के साथ–साथ भूमि जल स्तर में सुधार होगा। इससे दूसरी हरित क्रांति में सहयोग मिलेगी। सामाजिक एवं शष्य वानिकी क्षेत्र में वृद्धि के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के विकास से पर्यावरण संतुलन में अपेक्षित सहयोग मिलेगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– प्रति बूँद अधिक फसल के तहत दक्षिण बिहार के कुल 17 ज़िले, यथा– बाँका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया,

रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, भागलपुर, लखीसराय, शेखपूरा, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, पटना एवं अरवल में प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– जलछाजन विकास अन्तर्गत वैसे जिले जहाँ परियोजना कार्य अंतिम चरण में है को संतृप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तावित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– प्रति बूँद अधिक फसल 2017–18 का कार्य अभिसरण के रुप में किया जा रहा है।

कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार :

महोदय, राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रयासशील है। हमारे देश में कृषि विश्वविद्यालय/समकक्षीय संस्थानों की संख्या 73 है। हम सबके लिये यह हर्ष का विषय है कि वर्ष 2017 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय को पूरे देश में 24वाँ स्थान प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय को प्राप्त इस उपलब्धि में सभी छात्र– छात्राओं, प्राध्यापकों, अनुसंधानकर्त्ताओं, प्रसार कर्मियों, वरीय पदाधिकारियों सहित राज्य एवं केन्द्र सरकार का अहम् योगदान है। वर्त्तमान में बिहार कृषि विश्वविद्यालय अपने पाँच कृषि महाविद्यालय तथा एक उद्यान महाविद्यालय के माध्यम से स्नातक कार्यक्रम में कुल 431 विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित कर रहा है। स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय कृषि संकाय के 13 विषयों में अध्यापन का कार्य संचालित कर रहा है। स्नातकोत्तर शिक्षा के अन्तर्गत कृषि संकाय के 06 विषयों में पी०एच०डी० की पढ़ाई भी हो रही है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय के 55 से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय पात्रता

परीक्षा उत्तीर्ण की है। पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी विभाग के दो छात्रों ने सी०एस०आई० आर० द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिष्ठित जे०आर०एफ० छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसी विभाग के एक छात्र ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ली जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2017–18 में विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में स्नातक वर्ग की सभी सीटों पर शत्–प्रतिशत नामांकन पहली बार हुआ है। जर्दालू आम, भागलपुर कतरनी धान, मगही पान एवं शाही लीची को भौगोलिक सूचक के आवंटन हेतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रयास किया जा रहा था। खुशी की बात है कि भारत सरकार की संस्था ने जर्दालू आम, भागलपुर कतरनी धान, मगही पान एवं शाही लीची को भौगोलिक सूचक के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। विश्वविद्यालय में वानस्पतिक उद्यान के उन्नयन तथा विभिन्न मूल्यवान एवं दुर्लभ पौधों के संकलन हेतु बिहार सरकार द्वारा परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान उद्यान का जीर्णोद्धार किया जायेगा, साथ ही विभिन्न प्रकार के मूल्यवान एवं दुर्लभ प्रजातियों के पौधों का संकलन किया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के शोध परिषद् द्वारा अनुशंसित तीसी के प्रभेद, सबौर तीसी–1 को सेंट्रल वेराइटी रिलीज कमिटी, भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण पूर्वी भारत के लिए अधिसूचित किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के शोध परिषद् ने चना फसल की एक किस्म सबौर चना–1 तथा आम की एक किस्म सबौर आम–1 को अनुशंसित किया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा वर्ष 2017–18 में कुल 6 उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियाँ कृषकों के लिए समर्पित की गई है।

राज्य सरकार द्वारा कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अधीन 01 कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, 01 कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 01 खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा 01 जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु कृषि रोड मैप 2017–2022 में आवश्यक राशि का प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही, राज्य में 3 नये कृषि विज्ञान केन्द्र गया, मुजफ्फरपुर तथा पूर्वी चम्पारण में स्थापित किये जा रहे हैं।

महोदय संक्षेप में वर्ष 2018–19 में कृषि विकास की प्राथमिकताओं को दोहराना चाहूँगा –

- ❖ राज्य में आधुनिक प्रभेदों के बीज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समग्र विकास नीति लागू किया जायेगा। इसके तहत धान तथा गेहूँ के साथ–साथ दलहन एवं तेलहन के आधुनिकत्तम बीज के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र में बीज उत्पादन के साथ–साथ निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा। बीज वाहन, विकास वाहन के माध्यम से किसानों तक कृषि तकनीक के साथ–साथ आधुनिक बीज का विस्तार किया जायेगा।
- ❖ गंगा नदी के दोनों किनारे पर अवस्थित गाँवों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर की स्थापना की योजना को लागू किया जायेगा। जैविक सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए इनपुट सब्सिडी योजना चलाई जायेगी। इस योजना के तहत किसानों को फसल मौसम से पूर्व अनुदान की राशि अग्रिम के रूप में उनके बैंक खाते में भेजी जायेगी, ताकि वे अपने

आवश्यकता के अनुरूप इनपुट की खरीद कर सकें। वर्मी कम्पोस्ट तथा जैव उर्वरक के प्रोत्साहन के साथ–साथ गोबर गैस की स्थापना के लिए योजना चलाई जायेगी।

❖ किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान राशि दी जायेगी। लघु एवं सीमांत किसान तथा महिला किसानों के लिए उपयुक्त यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई जायेगी। गाँव स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जायेंगे।

❖ बागवानी के विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के साथ–साथ मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना चलाई जायेगी। इसके तहत नये बागानों की स्थापना के साथ–साथ कटाई के उपरांत वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के लिए योजना कार्यान्वित की जायेगी।

❖ जलछाजन के आधार पर मिट्टी एवं जल संरक्षण के कार्यक्रम चलाये जायेंगे। पुराने जलछाजन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर संतृप्त किया जायेगा। सिंचाई जल के महत्तम उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा।

❖ राज्य के सभी किसानों को मिट्टी जाँच के आधार पर स्वायल हेल्थ कार्ड दिये जायेंगे। साथ ही स्वायल हेल्थ कार्ड के उपयोग के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

❖ आधुनिक कृषि तकनीक के प्रचार–प्रसार के लिए जिला स्तर पर आत्मा तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जायेगा। पंचायत स्तर पर किसान चौपाल लगाये जायेंगे। पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय भी स्थापित किया जायेगा, ताकि किसानों को अपने ही पंचायत

में सभी प्रकार के कृषि योजनाओं की जानकारी एवं आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके। किसानों को समूहों में संगठित किया जायेगा तथा किसान समूहों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाये जायेंगे। फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी बनाये जायेंगे तथा मानक फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी को बीज राशि (Seed Money) दिया जायेगा। राज्य से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुदान देने पर विचार किया जायेगा।

❖ कृषि के क्षेत्र में नवाचारी पद्धतियों को बढ़ावा दिया जायेगा। प्रगतिशील किसानों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जायेगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों के हुनर को बढ़ाया जायेगा तथा उन्हें नवाचारी पद्धतियों में प्रशिक्षित किया जायेगा। नवनियुक्त कृषि समन्वयकों एवं किसान सलाहकारों को प्रशिक्षित किया जायेगा तथा उन्हें किसानों की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाया जायेगा।

❖ तीसरे कृषि रोड मैप के अधीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत गया में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय तथा सामुदायिक विज्ञान/फुड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय तथा आरा में जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। राज्य में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए प्रशिक्षित मानव बल को तैयार करने हेतु पोस्ट ग्रैजुएट स्तर पर छात्रवृत्ति की योजना चलाई जायेगी।

❖ किसानों की आमदनी को दोगुणा करने के लिए इन्द्रधनुषी क्रांति के लिए समेकित कृषि प्रणाली पर बल दिया जायेगा तथा इसे अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण के साथ–साथ आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

- सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं कृषि महाविद्यालयों में समेकित कृषि प्रणाली का मॉडल विकसित कर किसानों को प्रशिक्षण देने के लिये समुचित व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- कृषि योजनाओं में विशेष फसल एवं खाद्य प्रसंस्करण को भी शामिल किया जायेगा।
- बिहार राज्य के 54 बाजार समितियों के चहारदीवारी, सड़क, रौशनी, पेयजल, नाला, वृक्षारोपण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- किसानों को ससमय मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु टेलिमेट्रीक वेदर स्टेशन की स्थापना की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति तथा सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। महोदय इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के संदेश का उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है–

''आप आज जो करते हैं, उस पर भविष्य निर्भर करता है।''

साथ ही, पं० दीनदयाल उपाध्याय के संदेश का भी उल्लेख करना चाहूँगा–

''बीज की एक इकाई विभिन्न रूपों में प्रकट होती है– जड़ें, तना, शाखाएँ, पत्तियाँ, फूल और फल, इन सबके रंग और गुण अलग–अलग होते हैं, फिर भी बीज के द्वारा हम इन सबके एकत्त्व के रिश्ते को पहचान लेते हैं।''

अंत में,

माननीय सदस्यगण,

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कृषि विभाग का बजट माँग पारित करने का अनुरोध करता हूँ।

आप सभी को धन्यवाद।

डॉ० प्रेम कुमार

1. दिनांक 17.03.2018 को माननीय प्रधान मंत्री के द्वारा बिहार को वर्ष 2015–16 में मक्का के रेकार्ड उत्पादन करने हेतु राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जायेगा।
2. उत्तर बिहार में किसानों को मक्का के फसल में ~~बीज~~ दाना नहीं आने के कारण उसके जॉच का आदेश ~~कृषि उत्पादन आयुक्त~~ को दिया गया है।
3. पान का फसल ठंड के कारण खराब हो गया था। सरकार ने कृषि विभाग द्वारा सर्वे कराया है ताकि उसे मुआवजा मिल सके।
4. किसानों को हार्टिकल्चर में बैंकों द्वारा ऋण की राशि मुहैया कराने में असहयोग के संबंध में।
5. कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान किया जा रहा है, जिसका अध्ययन विभाग द्वारा किया जायेगा। वैज्ञानिकों के सहयोग से किसानों की आमदनी दुगुना करने में सहयोग लिया जायेगा।
6. किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रखंड स्तर पर कैम्प लगाकर दिया जायेगा।
7. केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में चार कृषि महाविद्यालय और तीन कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने पर विचार किया जा रहा है।
8. केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 600 सौ करोड़ तीन वर्षों में यांत्रिकरण हेतु राशि प्रधान मंत्री विशेष पैकेज के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है।
9. समेकित कृषि प्रणाली के लिए प्रयास किया जायेगा।
10. ~~नीलगाय~~ घोड़परास से फसलों के क्षति रोकने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है।
11. राज्य के दक्षिण बिहार के 17 जिलों में चल रहे 123 योजनाओं के अलावे 332 योजनाओं का डी0पी0आर0 तैयार कराकर नाबार्ड के सहयोग से किसानों का सिंचाई हेतु वर्षा जल के संचय पर कार्य योजना बनाया जा रहा है। 6।
12. बिहार के बैंकों निदेशित किया गया है कि किसानों को कृषि कार्य हेतु ऋण की सुबिधा मुहैया कराये।

कृषि सुविधा — 3,00,000 तक की राशि पर 7% ब्याज लगता है जिसमें भारत सरकार द्वारा 3% तथा बिहार सरकार द्वारा 1% ब्याज का वहन किया जाता है अर्थात्
Interest subvention — 3% — भारत सरकार, 1% — बिहार सरकार

13.किसानों के सफलता की कहानी एवं कृषि योजनाओं की जानकारी के लिए संदेश हेतु त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जायेगा।

14.योजनाओं की स्वीकृति में सिंगल विण्डो सिस्टम की तरह सुबिधा प्रदान की जायेगी।

15.कृषि समन्वयक पदों पर एवं किसान सलाकारों के पदों पर ए0टी0एम0 और विश्वविद्यालय/कॉलेजों की स्वीकृत पदों पर शीध्र नियुक्ति की प्रक्रिया अपना कर उन पदों पर बहाली की जायेगी।

16.प्रगतिशील किसानों को पारदर्शी तरीके से सम्मानित किया जायेगा।

17.राज्य के सभी पंचायतों में किसान के सहयोग के लिए कृषि पंचायत कार्यालय का शुभारंभ किया जायेगा।

18.किसानों को अलग से कृषि फीडर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति कराई जायेगी।

19.कृषि उत्पादन बाजार समिति, गया में पान के किसानों को मण्डी उपलब्ध कराई जायेगी।

20.बाढ़ से किसानों की क्षति का पैसा किसानों के खातों में भेज दी गई है।

21.चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, तेलहन, फल–फूल औषधि [illegible]

22.जैविक खेती करने वालों किसानों को भण्डार एवं बाजार की सुविधा कराई जायेगी।

23.तीसरा कृषि रोड मैप में कृषि के उत्पादन में बृद्धि एवं 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी की जायेगी।

24.कृषि एक्सटेंशन के संबंध में।